● वर्ष-5
● अंक-279
रायपुर, गुरुवार
09 जुलाई 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> शासकीय सेवकों के लिए...

साय कैबिनेट की बैठक में कई विधेयकों को मंजूरी

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मंत्रिपरिषद् ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों से खरीदी जा रही बिजली के भुगतान की सुरक्षा के लिए वर्तमान त्रिपक्षीय अनुबंध के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप डायरेक्ट डेबिट मैंडेट व्यवस्था लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से एनटीपीसी सहित अन्य सीपीएसयू से विद्युत आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित होगी तथा भुगतान सुरक्षा की व्यवस्था आरबीआई के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप हो सकेगी। राज्य शासन पर इससे कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा, क्योंकि वितरण कंपनी द्वारा भुगतान की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी तथा आवश्यक होने पर पहले लेटर ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाइटर्स), फाइटर आरक्षक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2026 में महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकृति दी गई है।

छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य होगा

निजी विश्वविद्यालय स्थापना

मंत्रिपरिषद् द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस संशोधन में भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के विनियमन प्रकोष्ठ की अनुशंसाओं के अनुरूप निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी प्रावधानों को अधिक व्यावहारिक, गुणवत्तापूर्ण और समकालीन बनाया गया है। इसके तहत निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विन्यास निधि के स्थान पर रक्षित निधि का प्रावधान लागू करने से अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के भविष्य को संवारने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जा सकेंगे। इसमें आधारभूत अधोसंरचना, पुस्तकालय एवं अन्य सुविधाओं को यूजीसी एवं सक्षम नियामक संस्थाओं के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का प्रावधान

किया गया है। इस संशोधन से राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार

मंत्रिपरिषद् ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस संशोधन के माध्यम से छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण को समाप्त करने के साथ ही उससे संबंधित प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। जीएसटी लागू होने के बाद वैट संबंधी द्वितीय अपीलों के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है और राज्य में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना भी हो चुकी है। ऐसे में पृथक वाणिज्यिक कर अधिकरण की आवश्यकता नहीं रह गई है। इस संशोधन के बाद अधिकरण में लंबित प्रकरणों का स्थानांतरण राजस्व मंडल को किया जाएगा, जिससे अपीलों के निराकरण की प्रक्रिया सुव्यवस्थित एवं अधिक प्रभावी हो सकेगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इस संशोधन का उद्देश्य जीएसटी कानून को सरल बनाना, अनुपालन संबंधी प्रक्रियाओं को आसान बनाना तथा करदाताओं, विशेषकर निर्यातकों और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले उद्योगों के लिए रिफंड प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है। इससे कर प्रशासन अधिक प्रभावी होगा, करदाताओं को सुविधा मिलेगी साथ ही राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस संशोधन का उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना, उद्योगों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करना तथा निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस संशोधन विधेयक के प्रारूप को तैयार करने में अन्य अग्रणी राज्यों की औद्योगिक नीतियों का भी अध्ययन किया गया है। इससे निवेश प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगी और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

मंत्रिपरिषद् की बैठक में छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनिमय-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, डिजिटल एवं समयबद्ध बनाना है। इस तरह का विधेयक लाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। इसके अंतर्गत डीम्ड परमिशन), स्व-प्रमाणीकरण, तृतीय-पक्ष सत्यापन, जोखिम-आधारित निरीक्षण तथा दोहरे लाइसेंसिंग दायित्वों को समाप्त करने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इससे निवेशकों के लिए अनावश्यक प्रक्रियात्मक बाधाएं कम होंगी, कारोबार करने में सुगमता बढ़ेगी तथा राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति मिलेगी।

जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण

मंत्रिपरिषद् ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य में अंगीकार करने के लिए विधानसभा में संकल्प प्रस्तुत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत सरकार द्वारा लाए गए इस संशोधन का उद्देश्य पर्यावरणीय कानूनों के अनुपालन को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इसके तहत छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाकर उन पर आर्थिक दंड का प्रावधान तथा दंड निर्धारण एवं अपील की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। इस निर्णय से राज्य में पर्यावरणीय नियमन को सरल बनाने, अनुपालन को प्रोत्साहित करने तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ प्रभावी पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

भाड़ा नियंत्रण अधिनियम

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य खाली मकानों को किराये पर देने को बढ़ावा देना और किरायेदारी से जुड़े विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। इस संशोधन में भवन स्वामी और किरायेदार के अधिकार व दायित्व स्पष्ट किए गए है, साथ ही संपत्ति प्रबंधक, किराया प्राप्ति, अधिकरण के अध्यक्ष की पदावधि और न्यायालय शुल्क से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए है। यह संशोधन भारत सरकार के आदर्श किरायेदारी अधिनियम, 2021 के अनुरूप है। मंत्रिपरिषद् द्वारा राजनांदगांव में 2000 सीट क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि के आबंटन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

मंत्रिपरिषद् ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूखंडों एवं निर्मित परिसरों पर देय ब्याज एवं अधिभार में राहत प्रदान करने हेतु वन टाइम सेटलमेंट योजना-2026 को मंजूरी दी है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने वाली पंडवानी की महान साधिका, पद्म विभूषण स्वर्गीय डॉ. तीजन बाई को बुधवार को रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय परिसर के मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित भव्य सांगीतिक श्रद्धांजलि समारोह में भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। लोककला, साहित्य और संस्कृति जगत की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में स्व. तीजन बाई के जीवन, साधना और उनके अद्वितीय सांस्कृतिक योगदान को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।

विस्तृत समाचार पेज-8 पर

2.5 किमी ऊंचाई से मुख्य पैराशूट का परीक्षण सफल

नई दिल्ली । भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल (अंतरिक्ष यात्रियों के कैप्सूल) के मुख्य पैराशूट का एक महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसरो ने बुधवार को बताया कि यह परीक्षण मंगलवार को मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (एडीआरडीई) के ड्रॉप जोन में किया गया। इसरो के अनुसार, इस परीक्षण का उद्देश्य यह जांचना था कि गगनयान के पहले मानव रहित मिशन जी-1 के दौरान अधिकतम भार की स्थिति में मुख्य पैराशूट सुरक्षित और तय मानकों के अनुसार काम करता है या नहीं।

इस परीक्षण के दौरान मुख्य पैराशूट की एक नमूना व्यवस्था और एक डमी भार को भारतीय वायु सेना के आईएल-76 विमान से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया। सबसे पहले ड्रोग पैराशूट खुला, जिसने नीचे गिर रहे क्रू मॉड्यूल को स्थिर किया और उसकी गति काफी कम कर दी। इसके बाद मुख्य पैराशूट खुला, जिससे डमी भार की रफ्तार और कम हुई और वह सुरक्षित गति से जमीन की ओर उतरा।

इसरो ने बताया कि गगनयान मिशन के लिए मुख्य पैराशूट की विश्वसनीयता जांचने के उद्देश्य से किए जा रहे एकीकृत एयरड्रॉप परीक्षणों की श्रृंखला में यह पांचवां परीक्षण (आईमैट-05) था। इस परीक्षण की सफलता से पहले मानव रहित गगनयान मिशन जी-1 के लिए मुख्य पैराशूट प्रणाली की क्षमता और विश्वसनीयता पर भरोसा और मजबूत हुआ है। गगनयान के क्रू मॉड्यूल में कुल 10 पैराशूट लगाए गए हैं, जो चार अलग-अलग प्रकार के हैं। इनमें दो एपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट हैं, जो पृथ्वी के वातावरण में दोबारा प्रवेश के दौरान पैराशूट वाले हिस्से की सुरक्षा करने वाले कवर को अलग करते हैं। इसके अलावा दो ड्रोग पैराशूट हैं, जो क्रू मॉड्यूल को स्थिर करते हैं और उसकी गति कम करते हैं।

क्रू मॉड्यूल में तीन पायलट पैराशूट भी लगे हैं। इनका काम तीन मुख्य पैराशूटों को बाहर निकालकर खोलना है। इसके बाद तीनों मुख्य पैराशूट पूरी तरह खुलते हैं और क्रू मॉड्यूल की गति को इतना कम कर देते हैं कि वह सुरक्षित तरीके से जमीन या समुद्र में उतर सके। यही प्रणाली भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेगी।

प्रमुख समाचार

पंजाब कांग्रेस में नहीं बदलेगा अध्यक्ष : भूपेश बघेल

चंडीगढ़। बुधवार को पंजाब कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की अटकलों को खारिज करते हुए कहा गया कि पार्टी हाईकमान का अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को राज्य इकाई का प्रमुख बनाए रखने का फैसला अंतिम है। पत्रकारों से बात करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि नेतृत्व से जुड़े फैसलों पर बार-बार पुनर्विचार नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि

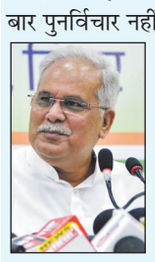

जब हाईकमान ने कोई फैसला ले लिया है, तो उसे बदला नहीं जाता। क्या यह गुड़िया-गुड्डे का खेल है कि बार-बार फैसला बदला जाएगा? यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस ने 1 जुलाई को घोषणा की कि वारिंग पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे, जबकि अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि चन्नी राज्य इकाई का प्रमुख न बनाए जाने से नाराज़ हैं। बघेल ने कहा कि वह जल्द ही चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा से मिलेंगे।

योगी ने कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का किया शुभारंभ

वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वाराणसी से प्रदेश के शिक्षकों व उनके परिजनों को मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना का तोहफा दिया। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ालालपुर में सुबह 10 बजे से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इसका

शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लागू होने के साथ ही प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। योजना में नियमित शिक्षकों के साथ शिक्षामित्र, अनुदेशक, रसोइया और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। सीएम योगी ने योजना का शुभारंभ करने के साथ ही माध्यममिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा के सभी शिक्षकों और बच्चों को हृदय से बधाई दी। कहा कि तीन योजनाएं हैं, कैशलेस चिकित्सा, डिबीटी, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। आपने मांगा नहीं लेकिन आपके स्वास्थ्य की चिंता हमें है।

पर्यावरण मंत्रालय बना प्रवचन मंत्रालय : जयराम रमेश

नईदिल्ली। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के चार करीबी सहयोगियों को दो दिनों के भीतर हटाए जाने के बाद, बुधवार को कांग्रेस ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय पर शासन-व्यवस्था के चरमराने का आरोप लगाया। पूर्व पर्यावरण मंत्री

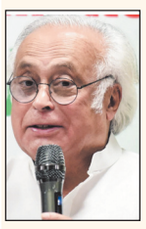

और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मंत्रालय देश के पर्यावरण और जंगलों की सुरक्षा करने में नाकाम रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण मंत्रालय अब प्रवचन मंत्रालय बन गया है। रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में, मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ़ में सभी अहम नियुक्तियों की जाँच पीएमओ करता है। अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के 4 करीबी सहयोगियों को लगातार दो दिनों में दो बैच में हटा दिया गया है। इनमें से एक सहयोगी को मंत्री का सबसे करीबी और भरोसेमंद व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि साफ़ है कि इस अहम मंत्रालय में कामकाज का सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है।

यूपी चुनाव 2027 के मद्देनजर सपा ने बनाई नई रणनीति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी ने बड़े वैचारिक और रणनीतिक बदलाव के संकेत दिए हैं। पार्टी ने अब विवादित मुद्दों से दूरी बनाते हुए हिंदू प्रतीकों के इस्तेमाल की सोची-समझी रणनीति पर अमल करना शुरू कर

दिया है। इस नई दिशा का सबसे ताजा उदाहरण राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे सपा आमजन के बीच खुद को सनातनी और हिंदू सरोकारों के प्रति संवेदनशील पार्टी के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है। राम मंदिर से जुड़े मामले पर पार्टी का रुख साफ करता है कि वह बहुसंख्यक समाज की आस्था से जुड़े विषयों पर बैकफुट पर रहने के मूड में नहीं है। सपा का यह बदला हुआ अंदाज आगामी चुनावों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीडीए के सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के साथ सनातनी प्रतीकों पर काम अपनाकर जनाधार बढ़ाने के उसके संजीदा प्रयासों का हिस्सा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सपा की यह नई राजनीतिक पिच उसे जमीन पर कितना फायदा पहुंचाती है।

अस्पताल में डॉक्टरों पर हमले को लेकर राउत ने सरकार पर तंज कसा

मुंबई। शिवसेना नेता संजय राउत ने कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक अस्पताल में महिला डॉक्टरों और नर्सों पर हुए हमले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने मिंधे गैंग के नाम से

जाने जाने वाले दोषियों के लिए कड़ी सज़ा की मांग की। मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, कृपया अपने पास मौजूद गृह मंत्री के पद का सम्मान करें! कोरोना के समय में लोगों की सेवा करने वालीं सफ़ेद कपड़ों में फ़रिश्तों जैसी महिला डॉक्टर और नर्सों को मिंधे गैंग के गुंडे अस्पताल में घुसकर बेरहमी से पीटते हैं- क्या यही कानून का राज है? उन्होंने मुख्यमंत्री फडणवीस से यह भी कहा कि उन सभी को हथकड़ी पहनाई जाए और उन्हें सिर्फ़ अंडरवियर और बनियान में सड़कों पर घुमाया जाए! इस बीच, शिवसेना के कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे ने केडीएमसी अस्पताल में महिला डॉक्टरों और नर्सों के साथ मारपीट के आरोपों से इनकार किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कैमरा एंगल की वजह से सीसीटीवी फुटेज शायद वैसा दिख रहा हो और ज़ोर देकर कहा कि अस्पताल के दौरे के दौरान उन्होंने किसी भी मेडिकल स्टाफ़ पर हाथ नहीं उठाया।

स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की प्रगति का व्यावहारिक रास्ता

श्रीपाद नाइक

वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता, ऊर्जा की बढ़ती मांग और जलवायु से जुड़ी गंभीर चुनौतियों के इस दौर में, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ऐसी ऊर्जा प्रणालियों का निर्माण करने की जरूरत है जो स्वच्छ व अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित, सस्ती एवं भरोसेमंद होने के साथ-साथ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विकास संबंधी जरूरतों तथा आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप भी हों।

स्वच्छ ऊर्जा दरअसल ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और दीर्घकालिक विकास की दृष्टि से तेजी से अहम होती जा रही है। यह ईंधन बाजार में आने वाले उतार-चढ़ाव से पैदा होने वाले जोखिमों को कम कर सकती है, ऊर्जा को अपेक्षाकृत अधिक सुलभ बना सकती है, रोजगारसृजित कर सकती है, घरेलू उद्योगों को मजबूत कर सकती है और देश को अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ बना सकती है। फिर भी, स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने के रास्ते एक जैसे नहीं हो सकते। इन रास्तों को राष्ट्रीय परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों और विकास की प्राथमिकताओं के हिसाब से निर्धारित किया जाना चाहिए। इसी बिंदु पर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच आपसी सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है।

ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच बेहतर सहयोग से स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समावेशी विकास के साझा लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत का अपना अनुभव यह बताता है कि स्वच्छ ऊर्जा की शुरुआत लोगों से ही होनी चाहिए। पिछले दशक में, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत लगभग 28.6 मिलियन घरों को बिजली के कनेक्शन दिए गए। इससे सभी तक बिजली पहुंचाने का काम आगे बढ़ा और ग्रामीण व कम सुविधा वाले इलाकों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को 105 मिलियन से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए। इससे खाना पकाने के साफ-सुथरे तरीकों को बढ़ावा मिला, घर में सेहत बेहतर हुई और कठिन श्रम का बोझ कम हुआ। ये पहल एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को रेखांकित करती हैं- स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने को केवल स्थापित मेगावाट या जोड़ी गई क्षमता के आधार पर नहीं मापा जा सकता, बल्कि इससे

पैदा हुए अवसरों, सुदृढ़ हुई आजीविका और बेहतर हुए जीवन स्तर के आधार पर भी मापा जाना चाहिए। लोगों को प्राथमिकता देने वाले इस दृष्टिकोण के साथ-साथ बड़े पैमाने पर काम और सहयोगी बुनियादी ढांचे की भी जरूरत है। भारत की स्वच्छ ऊर्जा की कहानी में नवीकरणीय ऊर्जा अहम हो गई है। लेकिन इसकी सफलता इसे समर्थन प्रदान करने वाली प्रणालियों पर निर्भर करती है। सौर और पवन ऊर्जा को तेजी से अपनाया जा सकता है, लेकिन इनकी पूरी क्षमता का लाभ तभी मिल पाएगा जब पारेषण , वितरण , भंडारण और ग्रिड प्रबंधन एकसाथ मिलकर काम करें। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार में सहायता प्रदान करने वाली प्रणालियों को मजबूत करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। पारेषण संबंधी बुनियादी ढांचे का निरंतर विस्तार हुआ है। इसके साथ-साथ ऊर्जा के भंडारणऔर ग्रिड की सुदृढ़ता के क्षेत्र में भी निवेश बढ़ा है। वितरण संबंधी सुधारों और उन्नत ग्रिड तकनीक को अपनाने से एक ऐसी बेहतर एवं भरोसेमंद ऊर्जा प्रणाली बनाने में मदद मिली है, जो नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी को समन्वित करने में सक्षम है। भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन पर आधारित क्षमता अब 288 गीगावॉट से अधिक हो गई है। बड़े पैमाने की परियोजनाओं के अलावा, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां ङ्क जैसे कि रूफटॉप सोलर, सोलर पंप, मिनी-ग्रिड और माइक्रो-ग्रिड - ग्रामीण और कम सुविधा वाले इलाकों में स्वच्छ ऊर्जा को और अधिक सुलभ बना रही हैं। ये प्रणालियां सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज, स्कूलों, हेल्थकेयर सेंटरों तथा स्थानीय व्यवसायों को मदद पहुंचाने के साथ-साथ ग्रामीण आजीविका और स्थानीय आर्थिक सुदृढ़ता को भी बढ़ावा दे रही हैं। भारत की 'पीएम सूर्य घर- मुफ्त बिजली योजना' बड़े पैमाने पर इस दृष्टिकोण को दर्शाती है। इस योजना से अब तक लगभग 4 मिलियन परिवारों को लाभ हुआ है, जिससे उपभोक्ता अपेक्षाकृत अधिक विकेन्द्रीकृत एवं भागीदारी वाली ऊर्जा प्रणाली में योगदान देने वाले बन पाए हैं। हालांकि, स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार में वित्त पोषण सबसे अहम तत्वों में से एक बना रहेगा। कई विकासशील देशों में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इन संभावनाओं को बड़े पैमाने पर लागू करने तथा बैंक से ऋण पाने योग्य परियोजनाओं में बदलने हेतु सस्ती और दीर्घकालिक पूंजी की जरूरत होती है। आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा, वितरण संबंधी बुनियादी ढांचा, ग्रिड के आधुनिकीकरण, भंडारण प्रणाली और कम ऊर्जा खर्च करने वाली तकनीकों में निवेश बेहद जरूरी होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे संस्थान वित्त पोषण, तकनीक संबंधी साझेदारी और क्षमता विकास के जरिए विकासशील देशों की मदद करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

अबूझमाड़ में नक्सलियों का बड़ा डम्प रिकवर

15 किलो का प्रेशर कुकर आईईडी, रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार बरामद

नारायणपुर। अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता मिली है। 53 वीं वाहिनी आईटीबीपी और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान के दौरान 15 किलोग्राम वजनी प्रेशर कुकर आईईडी, देसी रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार राउंड और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की है। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही आईईडी को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया, जिससे एक संभावित बड़ी दुर्घटना टल गई। 31 मार्च 2026 को बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज होने के बाद भी अबूझमाड़ के दुर्गम जंगलों में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक अब भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बने हुए हैं।

इन्हीं खतरों को समाप्त करने के उद्देश्य से लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। खुफिया सूचना के आधार पर 53वीं वाहिनी आईटीबीपी के कमांडेंट संजय कुमार के मार्गदर्शन में 7 जुलाई की सुबह अड़िंगपार कैंप से ग्राम एडसमेटा और आसपास के जंगलों की ओर विशेष एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग (ADP) अभियान शुरू किया गया। सहायक कमांडेंट (जीडी) आजाद सिंह के नेतृत्व में निकले इस संयुक्त अभियान में आईटीबीपी के 34 जवान, छत्तीसगढ़ पुलिस का एक प्रतिनिधि और पांच सदस्यीय बम निरोधक दस्ता (BDDS) शामिल था। सुबह लगभग 5 बजे शुरू हुई सर्चिंग के दौरान निर्धारित स्थान पर जवानों को नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री मिली। सबसे खतरनाक बरामदगी 15 किलोग्राम वजनी प्रेशर कुकर आईईडी रही, जिसे सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया गया था।स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए नियंत्रित विस्फोट के माध्यम से आईईडी को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने एक स्थानीय स्तर पर निर्मित रॉकेट लॉन्चर, 16 देशी 51द्वद्व मोर्टार राउंड, 5 देशी 84 द्वद्व रॉकेट लॉन्चर राउंड, 10 देशी 40म46 द्वद्व बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (क्व्नरु) राउंड, ।303 राइफल के 8 कारतूस और 4 सामरिक पाउच भी बरामद किए। बरामद सामग्री से स्पष्ट है कि नक्सली सुरक्षा बलों पर बड़े हमले की तैयारी में थे।

पूरे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने अत्यधिक सतर्कता और पेशेवर दक्षता का परिचय दिया। अभियान सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद शाम लगभग 4:30 बजे सभी जवान सुरक्षित अड़िंगपार कैंप लौट आए। बरामद हथियारों और विस्फोटकों को नियमानुसार जब्त कर आगे की जांच की जा रही है।

अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाकों में लगातार चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों से यह स्पष्ट हो रहा है कि सुरक्षा बल नक्सलियों के नेटवर्क और उनके छिपाए गए हथियारों के जखीरे को लगातार ध्वस्त कर रहे हैं। 15 किलोग्राम के शक्तिशाली आईईडी और भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी ने एक बार फिर साबित किया है कि समय रहते की गई कार्रवाई से एक बड़ी जनहानि और सुरक्षा बलों पर संभावित हमला टाल दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन और निगरानी को और अधिक तेज करने की बात कही है।

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और दो आईएएस अधिकारियों समेत 4 के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर

सक्ती। जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट से जुड़े भू-विस्थापितों ने वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल समेत चार पक्षों के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के तहत पात्र भू-विस्थापितों को भत्ता या अन्य लाभ उपलब्ध नहीं कराए गए। याचिका में वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के अलावा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन सचिव शम्मी आबिदी, सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो तथा डभरा एसडीएम को भी पक्षकार बनाया गया है।

मामला सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट से जुड़ा है, जिसे पहले एथेना पावर प्लांट के नाम से जाना जाता था। जानकारी के अनुसार, प्लांट की स्थापना के लिए वर्ष 2008 में आसपास के गांवों की लगभग 1,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इस प्रक्रिया में 800 से अधिक परिवारों ने अपनी जमीन दी थी। भू-विस्थापितों का कहना है कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति-2007 के तहत प्रभावित परिवारों को नौकरी अथवा नियमानुसार भत्ता दिया जाना था, लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिला। याचिका के अनुसार, एथेना पावर प्लांट का संचालन वर्ष 2013 में शुरू हुआ था, लेकिन वित्तीय संकट के चलते वर्ष 2016 में इसे बंद करना पड़ा। बाद में वर्ष 2022 में वेदांता ग्रुप ने इस प्लांट का अधिग्रहण किया और वर्ष 2025 में इसका संचालन दोबारा शुरू किया।

भू-विस्थापितों का आरोप है कि प्लांट दोबारा शुरू होने के बाद भी 400 से अधिक परिवारों को न तो रोजगार दिया गया और न ही नियमानुसार भत्ता उपलब्ध कराया गया। उनका कहना है कि वे पिछले 13 वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित हैं।

भू-विस्थापित परिवारों के अनुसार, वर्ष 2021 में 37 परिवारों की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। करीब दो वर्ष बाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और राज्य शासन को मामले के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इतिहास

इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा गठित समिति ने प्लांट प्रबंधन को पत्र जारी कर पात्र भू-विस्थापितों को नियमानुसार भत्ता देने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया।

भू-विस्थापितों का कहना है कि लगभग दो माह पहले सक्ती कलेक्टर ने भी प्लांट प्रबंधन को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पात्र परिवारों को भत्ता देने के निर्देश दिए थे। आरोप है कि इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी के बाद प्रभावित परिवारों ने न्यायालय की अवमानना याचिका दायर करने का निर्णय लिया।

पूरे मामले पर सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन की ओर से प्लांट प्रबंधन को पत्र जारी कर भू-विस्थापितों को नियमानुसार भत्ता भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन मामले के निराकरण के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

फिलहाल मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में होना बाकी है। याचिका में लगाए गए आरोपों पर संबंधित पक्षों की ओर से न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया जाना है।

सड़क पर कांग्रेस का प्रदर्शन

बिलासपुर। बिल्हा विधानसभा क्षेत्र का कड़ार सेवार मुख्य मार्ग सालों से बदहाल पड़ा है। बारिश के कारण सड़क में बने गड्ढों में जगह जगह पानी भर गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी खस्ताहाल सड़क को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। बिलासपुर से बलौदाबाजार जाने वाले मुख्य मार्ग पर बने गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने के बाद कांग्रेसी खुद गड्ढों में उतर गए और वहीं बैठकर प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेसियों ने प्रतीकात्मक रूप से गड्ढों में मछली पकड़ने के लिए जाल फेंककर विरोध प्रदर्शन किया। इस अनोखे प्रदर्शन ने राहगीरों का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। प्रदर्शन के दौरान ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष लक्ष्मीनाथ साहू ने आरोप लगाया कि यह सड़क क्षेत्र के हजारों लोगों के आवागमन का प्रमुख मार्ग है, लेकिन कई वर्षों से इसकी हालत बेहद जर्जर बनी हुई है। बरसात के मौसम में सड़क पर बने गहरे गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों, स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को रोजाना जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग और जनप्रतिनिधियों ने सड़क की सुध नहीं ली। वहीं सड़क पर कांग्रेस के प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। बोदरी तहसीलदार संदीप साय ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए यहां आए है, ज्ञापन मिलने के बाद कार्रवाई करेंगे।

जमीन पर लिटाकर इलाज का वीडियो वायरल

सूरजपुर। जिले में झोलाछाप डॉक्टरों और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल मरीज का जमीन पर लिटाकर इलाज करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला भैयाथान जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत बुंदिया है। बताया जा रहा है कि एक मेडिकल दुकान में कथित झोलाछाप चिकित्सक ने मरीज को फर्श पर लिटाकर इलाज किया। जानकारी के मुताबिक संबंधित व्यक्ति मेडिकल दुकान की आड़ में मरीजों का उपचार करता है। हालांकि अभी तक यह आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसके पास इलाज की वैध डिग्री या मंजूरी है या नहीं। मामला सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कपिल देव पैकरा ने मामले को गंभीर बताते हुए वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और स्वास्थ्य विभाग तथ्यों को जुटाने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं, तब भी लोग निजी और कथित झोलाछाप चिकित्सकों के पास इलाज कराने को क्यों मजबूर हो रहे हैं।

रातभर अकेले हाथी ने मचाया उत्पात

कोरबा। कटघोरा वन मंडल के पसान वन परिक्षेत्र में मंगलवार देर रात एक हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। मरवाही के झुंड से बिछड़कर आए इस अकेले हाथी ने तरई नार और पिपरहा गांव में तोड़फोड़ की। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। हाथी के गांव में घुसते ही कई कच्चे-पक्के मकान क्षतिग्रस्त हो गए। एक पक्के मकान की दीवार भी हाथी ने तोड़ डाली। हाथी के चिल्लाने और घर तोड़ने की आवाज से पूरा गांव दहशत में आ गया। लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। प्रभावित परिवारों ने रात जागकर बिताई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन अमले ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद हाथी को गांव से बाहर खदेड़ा। वनकर्मियों की सूझबूझ से बड़ी जनहानि टल गई।

विशेष जांच के दौरान यातायात नियम तोड़ने वाले 62 लोगों का काटा चालान

सड़क सुरक्षा के लिए दिलाई शपथ

बीजापुर। सड़क सुरक्षा को लेकर बीजापुर पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। विशेष जांच अभियान के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले 62 वाहन चालकों के चालान काटे गए, जिनसे कुल 27,200 का समन शुल्क वसूला गया। बता दें कि यह विशेष अभियान पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव के मार्गदर्शन में संचालित किया गया। जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई डीएसपी एवं यातायात नोडल अधिकारी विनीत साहू के नेतृत्व में की गई। अभियान के दौरान यातायात प्रभारी केशव ठाकुर, सहायक उप निरीक्षक विजय मंडावी सहित यातायात शाखा के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए चालान जारी किए गए। पुलिस ने कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता अभियान भी चलाया। इस दौरान वाहन चालकों और आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा के महत्व और यातायात नियमों की जानकारी दी गई। लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने तथा अन्य यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही सभी को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई गई। बीजापुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन कर न केवल अपनी, बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के विशेष जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

अनोखी परंपरा:मेंढक मेंढकी की शादी में झूमा पूरा गांव

सूरजपुर। किसानों के लिए बारिश खुशी लाती है।बारिश के समय प्रकृति का रंग पूरी तरह निखर जाता है।हरे भरे वन और कल-कल करती नदियां लोगों को अपनी ओर खींचती है।आज के आधुनिक युग में भी अच्छी बारिश के लिए पुरानी परंपरा और रीति रिवाज निभाए जाते हैं,ऐसी ही एक परंपरा का निर्वहन सूरजपुर में हुआ। सूरजपुर जिले में अच्छी बारिश की कामना को लेकर एक अनोखी परंपरा देखने को मिली। बारिश में हो रही देरी और खेती-किसानी की चिंता ने ग्रामीणों को परेशानी में डाल दिया था।इसलिए ग्रामीणों ने अच्छी बारिश के लिए सदियों पुरानी परंपरा को एक बार फिर निभाया। ग्रामीणों ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से मेंढक और मेंढकी का पूरे रीति-रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह कराया।इस अनोखी शादी में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और पूरे आयोजन को पारंपरिक विवाह की तरह धूमधाम से संपन्न कराया गया। शादी के दौरान मेंढक मेंढकी को दूल्हा-दुल्हन की तरह सजाया गया ।इसके बाद बाजे-गाजे के साथ बारात निकाली गई।

रिजमेरगढ़ में ईको-फ्रेंडली रिसॉर्ट की तरह डेवलपमेंट

गौरेला पेंड्रा मरवाही। जिले की सबसे ऊंची चोटी राजमेरगढ़ मानसून के मौसम में और भी खूबसूरत हो जाती है। अद्भुत प्राकृतिक छटा के कारण बारिश में पर्यटकों के लिए ये आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गई है। समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस स्थल को रूफ ऑफ जीपीएम के नाम से भी जाना जाता है। यहां सूर्योदय और सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक पहुंचते हैं, वहीं बारिश के दिनों में यहां का नजारा किसी हिल स्टेशन से कम नहीं दिखाई देता। मानसून के दौरान राजमेरगढ़ की वादियां घने बादलों और धुंध की चादर में लिपटी रहती हैं। कई बार बादल पहाड़ी के नीचे घाटियों में तैरते नजर आते हैं तो कभी तेज हवाओं के साथ पहाड़ियों को छूते हुए ऊपर उठते दिखाई देते। राजमेरगढ़ में बैगा कुटीर समेत निर्माण कार्य के लिए कुल 42 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। इसमें 4 कॉटेज के निर्माण किए जा रहे हैं। छ्स्नह्र ने बताया कि पहले भी निर्माण की कोशिश हुई थी लेकिन हवा के दबाव के चलते वहां रूफिंग नहीं टिक पा रही थी।

जगदलपुर में 19 साल का नकाबपोश झपटमार गिरफ्तार

जगदलपुर। शहरी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से आतंक का पर्याय बने एक शातिर नकाबपोश बाइक सवार झपटमार को गिरफ्तार करने में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पकड़े गए आरोपी की पहचान 19 वर्षीय राजमन यादव, निवासी ग्राम कुथर (थाना मारडूम) के रूप में हुई है, जो अपने दोस्तों के साथ घूमने-फिरने के शौक और पैसों की चाहत में इन वारदातों को अंजाम दे रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों के कड़े दिशा-निर्देशन में मुस्तैद कोतवाली और साइबर की संयुक्त टीम ने त्वरित घेराबंदी करते हुए आरोपी को दलपत सागर से पावर हाउस चौक के पास से दबोच लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने विभिन्न वारदातों में लूटे गए लगभग 2.5 लाख रुपये मूल्य के आभूषण और सामान बरामद किए हैं। जगदलपुर एएसपी माहेश्वर नाग ने बताया कि यह शातिर अपराधी मुख्य रूप से शहर के सुनसान और अंधेरे रास्तों को चुनता था। जहां पैदल या अकेले जा रही लड़कियों और महिलाओं को निशाना बनाना आसान हो।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं मिला मानदेय लगाई गुहार

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। पिछले दो महीने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। यही नहीं पिछले एक वर्ष से आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन का किराया भी बकाया है। भुगतान लंबित होने के कारण अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना एक समस्या है। अपनी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं, लेकिन करीब दो घंटे तक इंतजार करने के बावजूद उनकी कलेक्टर संतन देवी जांगड़े से मुलाकात नहीं हो सकी। इससे नाराज और मायूस महिलाओं को बिना मुलाकात किए लौटना पड़ा।आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि नियमित मानदेय नहीं मिलने से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है समस्या केवल मानदेय तक सीमित नहीं है। जिले के कई आंगनबाड़ी केंद्र निजी भवनों में संचालित हो रहे हैं, जिनका लगभग एक वर्ष से किराया नहीं चुकाया गया है।

बारिश के लिए बस्तर में 84 गांव की अनोखी परम्परा

दंतेवाड़ा। एल नीनो की वजह से इस बार मानसून पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है। मानसून के कमजोर पड़ने से किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं। रुठे मानसून और बारिश के देवता इंद्रदेव (स्थानीय भाषा में जिसे आदिवासी लोग भीमसेन देव कहते हैं) को मनाने के लिए दंतेवाड़ा में अनोखी पूजा परंपरा निभाई गई। इस अनोखी पूजा परंपरा में 84 गांवों के लोग शामिल हुए।मान्यता है कि इस अनोखी पूजा परंपरा को निभाने से बारिश के देव इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और जमकर बारिश होती है। बारिश की वजह से अच्छी फसल होती है और किसानों के घर सुख और समृद्धि का वास होता है। इस अनोखी पूजा परंपरा में शामिल होने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि पूर्वजों के समय से ये परंपरा निभाई जाती रही है, जिसका पालन वो भी करते आ रहे हैं। गांव के लोग बताते हैं कि यह परंपरा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि दक्षिण बस्तर के आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान और प्रकृति के प्रति उनके गहरे विश्वास का प्रतीक भी है।

भूस्खलन और जहरीली गैस के खतरे से चिरमिरी बरतूंगा मुख्य मार्ग बंद

3 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित

एमसीबी। कोयलांचल क्षेत्र चिरमिरी में बरतूंगा मुख्य मार्ग को भूस्खलन और संभावित दुर्घटना की आशंका के चलते अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एसईसीएल (स्श्वष्टरु) चिरमिरी ओपन कास्ट प्रबंधन ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है। प्रशासन ने भी आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक मार्ग से आवागमन के निर्देश जारी किए हैं।

चिरमिरी-बरतूंगा मुख्य मार्ग से लगे ओपन कास्ट माइंस क्षेत्र में कई स्थानों पर जमीन में दरारें आ गई हैं। इन दरारों से गैस निकलने की भी जानकारी सामने आई है। लगातार हो रही बारिश के कारण मिट्टी और चट्टानों के कटाव से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में सड़क से गुजरना जोखिमपूर्ण मानते हुए एसईसीएल प्रबंधन ने मार्ग को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है।

उप क्षेत्रीय प्रबंधक, चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस अरुण सिंह चौहान ने बताया कि लगातार बारिश के कारण खदान क्षेत्र से लगी जमीन में दरारें और धंसान की स्थिति उत्पन्न हुई है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एहतियात के तौर पर मुख्य मार्ग को अस्थायी रूप से बंद किया गया है।

उप क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि वैकल्पिक रास्ते से दूरी बढ़ी है लेकिन दूरी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी लोगों की सुरक्षा है, लोगों से अपील है कि अपनी जान की सुरक्षा सुनिश्चित करें और वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें। अधिकारी ने बताया कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होगा, आवागमन बहाल करने पर निर्णय लिया जाएगा।

वहीं सड़क बंद होने से बरतूंगा क्षेत्र के लगभग 3,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी डीएवी पब्लिक स्कूल के करीब 1,500 विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को होगी, जिन्हें अब प्रतिदिन लगभग 5 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय कर स्कूल और अन्य गंतव्यों तक पहुंचना पड़ेगा। इसके अलावा क्षेत्र के कर्मचारी, व्यापारी और आम लोगों की दैनिक आवाजाही भी प्रभावित होगी।

हाईकोर्ट से 7 आरोपियों को मिली सशर्त अग्रिम जमानत

बिलासपुर। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने धमतरी जिले की वर्ष 2007 की शिक्षाकर्मी ग्रेड-3 भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े 18 साल पुराने मामले में सात आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बैंच ने कहा कि इसी मामले में समान आरोपों वाले अन्य सह-आरोपियों को पहले ही राहत मिल चुकी है, इसलिए वर्तमान याचिकाकर्ताओं को भी जमानत का लाभ दिया जाना उचित है। कोर्ट ने सात अलग-अलग आपराधिक अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। दरअसल, वर्ष 2007 में जनपद पंचायत मगरलोड में शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के 172 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई थी। आरोप है कि चयन समिति के सदस्यों और अन्य आरोपियों ने साजिश के तहत कुछ अभ्यर्थियों के फर्जी या अमान्य दस्तावेजों के आधार पर अंक बढ़ाकर उन्हें चयनित करा दिया, इसके चलते पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली और वे बाहर हो गए। इस संबंध में वर्ष 2011 में पुलिस थाना मगरलोड में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(9)(4) के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत कई समितियों और स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद हुई थी। करीब 5,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनकी अलग-अलग स्तर पर जांच के बाद अंतिम चयन सूची बनाई गई थी। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया, पुलिस ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि याचिकाकर्ताओं ने किसी आपराधिक षड्यंत्र में भाग लिया था।

संक्षिप्त समाचार

भाजपा सहयोग केंद्र में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सुनी लोगों की समस्याएं

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश

कार्यालय के सहयोग केंद्र में बुधवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आमजनों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान शिविर में 300 से अधिक लोग अपनी समस्याएं और मांगों को लेकर पहुंचे। वित्त मंत्री ने 100 से अधिक आवेदनों का तत्काल निराकरण कराया, जबकि अन्य आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजकर शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। मीडिया से चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि कई मामलों में तत्काल संबंधित अधिकारियों को फोन कर समस्याओं का समाधान कराया गया। वहीं 100 से अधिक मांग संबंधी आवेदनों को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर उनके जल्द निराकरण की प्रक्रिया शुरू कराई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और सहयोग केंद्र इसी उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है, ताकि लोगों को एक ही स्थान पर अपनी समस्याओं के समाधान का अवसर मिल सके। आज सहयोग केंद्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक बजाज और प्रबल प्रताप जूदेव भी मौजूद रहे।

8 आईएएस-10 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का तबादला

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 8 अधिकारियों और राज्य प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। सीनियर आईएएस अधिकारी रिमिजियस एक्का को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के साथ राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गजेंद्र सिंह ठाकुर को राजस्व, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग का उप सचिव बनाया गया है। प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। सुरूचि सिंह को नगर पालिक निगम भिलाई का आयुक्त बनाया गया है। वहीं, जयंत नाहटा को जिला पंचायत धमतरी, एम. भार्गव को जिला पंचायत दंतेवाड़ा, तन्मय खन्ना को जिला पंचायत बस्तर और दुर्गा प्रसाद अधिकारी को जिला पंचायत राजनांदगांव का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में भी बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। इंद्रजीत बर्मन को स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में नई जिम्मेदारी दी गई है। राजीव कुमार पांडेय को उच्च शिक्षा संचालनालय में पदस्थ किया गया है।भारती चंद्राकर को मार्कफेड, दिनेश कुमार नाग को छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन और नयनतारा सिंह तोमर को चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अहिवारा के मानिक मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निरस्त

रायपुर। दुर्ग जिले के अहिवारा स्थित मेसर्स मानिक मेडिकल स्टोर्स का औषधि लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक के निर्देश पर की गई। जानकारी के अनुसार, 16 जून को सहायक औषधि नियंत्रक और औषधि निरीक्षक ने बस स्टैंड के सामने स्थित मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अन्य दवाओं के साथ एक एमटीपी (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी) किट बरामद हुई, लेकिन संचालक इसके क्रय-विक्रय से संबंधित कोई वैध रिकॉर्ड या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद 24 जून को फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 30 जून को दिए गए जवाब में भी संचालक संबंधित दवा के वैध बिल या अभिलेख उपलब्ध नहीं करा पाया। इसे अधिनियम और नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए 6 जुलाई को मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।

बाल संरक्षण आयोग में सदस्य बने मनमथनाथ शर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निगम, मंडल, आयोग के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की

गई है। जारी आदेश के मुताबिक जांजगीर के जाने माने अधिवक्ता मनमथनाथ शर्मा को राज्य बाल संरक्षण आयोग में सदस्य (एकल) नियुक्त किया गया है। सामाजिक क्षेत्र में लगातार सक्रिय श्री शर्मा के मनोनयन पर छत्तीसगढ़ के अधिवक्ता बिरादरी में काफी हर्ष है। इस नियुक्ति के लिए उन्होने राज्य सरकार के प्रति आभार जताया है।

छत्तीसगढ़ में एनएसएस गतिविधियों को मिलेगी रफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना (ह्रस्) की गतिविधियों को और अधिक सुचारू, प्रभावी और गतिशील बनाने के लिए राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 29 अंशकालीन जिला संगठकों की नियुक्ति की गई है, जिसमें संबंधित प्राध्यापकों व व्याख्याताओं को उनके वर्तमान शैक्षणिक दायित्वों के साथ-साथ आगामी 02 वर्षों के लिए जिला संगठक की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पीडब्ल्यूडी के सचिव ने रेलवे ओवर-ब्रिज एवं अंडर-ब्रिज कार्यों की समीक्षा की

कार्यों में तेजी लाने लोक निर्माण विभाग और रेलवे के अधिकारियों को बेहतर समन्वय से काम करने के दिए निर्देश

- स्कार्यस्थलों में आ रहे अवरोधों को तत्परता से दूर कर अप्रारंभ कार्यों को जल्दी शुरू करने कहा

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने विभाग के सेतु परिक्षेत्र और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदेश में रेलवे ओवर-ब्रिज (ऋह्क) और रेलवे अंडर-ब्रिज (ऋक्क) के निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आज हुई बैठक में रेलवे ओवर-ब्रिज और रेलवे अंडर-ब्रिज के कार्यों में तेजी लाने लोक निर्माण विभाग और रेलवे के अधिकारियों को बेहतर समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यस्थलों की बाधाओं को तत्परता से दूर कर अप्रारंभ कार्यों को जल्दी शुरू करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी और दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे के बिलासपुर मुख्यालय के प्रधान मुख्य अभियंता श्री अवनीश कुमार पाण्डेय भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक में विभागीय और रेलवे के अधिकारियों को आपसी समन्वय को और मजबूत करते हुए निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाते हुए उन्हें शीघ्र पूरा करने को कहा, ताकि लोगों को जाम और रेलवे फाटकों पर होने वाली असुविधा से राहत मिल सके। इससे माल परिवहन भी अधिक सुगम और तेज होगा।

विभागीय सचिव ने नए आरओबी और आरयूबी के कार्यों को जल्द शुरू करने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर बाधाओं का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यस्थलों से अतिक्रमण हटाने, भूमि व्यपवर्तन, नामांतरण तथा भू-अर्जन जैसी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के साथ समयबद्ध ढंग से पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रगतिरत परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण कर प्रदेश में आवागमन को अधिक सुरक्षित, सुगम, सुव्यवस्थित और तेज बनाना राज्य शासन की प्राथमिकता में है।

श्री बंसल ने कार्यस्थलों पर यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी शिफ्टिंग में देरी के कारण निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित परियोजनाओं के प्राक्कलन तथा ड्राइंग-डिजाइन तैयार करने के लिए जहां भी लोक निर्माण विभाग और रेलवे के अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण की जरूरत हो, वहां तत्काल संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने को कहा।

उन्होंने रेलवे ओवर-ब्रिज और रेलवे अंडर-ब्रिज परियोजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण करने नियमित और कड़ाई से मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और रेलवे के अधिकारियों को हर तीन महीने में बैठक कर कार्यों की प्रगति का आकलन करने और लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव, सेतु परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री एस.के. कोरी, अधीक्षण अभियंता श्री डी.के. माहेश्वरी, दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे के बिलासपुर मुख्यालय के मुख्य अभियंता श्री मनोज कुमार सिंह, सीपीएम-बिलासपुर श्री राजीव कुमार और सीपीएम-रायपुर श्री तत्वदर्शी साहू भी बैठक में मौजूद थे।

पीएम आवास 2.0 लैंड टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न

- पात्र आवासहीन परिवारों को पक्का घर मिले यह सुनिश्चित हो

रायपुर। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री आवास 2.0 भूमि टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय प्रोजेक्ट के लिए भूमि के सर्वेक्षण एवं चिन्हांकन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टरों को प्रधानमंत्री आवास 2.0 के लिए हितग्राही की पहचान कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। उन्होंने आबादी भूमि पर रहने वाले पात्र हितग्राहियों को ढूंढकर सत्यापन करना एवं उन्हें आवास उपलब्ध कराने के लिए समूचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को नगरीय निकायों में वर्तमान और भविष्य की आवासीय आवश्यकता का आंकलन कर कार्ययोजना बनाने कहा है। जिससे समय पर हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराये जा सकें। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में योजनांतर्गत हितग्राहियों की पहचान कर आवश्यकतानुसार आवास बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए है। बैठक में नगरीय एवं प्रशासन विकास विभाग की सचिव श्रीमती आर.शंगीता, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

थ्री डी संयंत्र में विस्फोट से 3 मजदूरों की मौत का मामला

मृतकों के परिवार को मिलेगा 30-30 लाख का मुआवजा

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के उरला स्थित थ्री डी फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 3 मजदूरों की मौत हो गई। घटना के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं मृतकों के परिवार को कारखना प्रबंधन ने आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा कर दी है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि उरला स्थित थ्री डी फैक्ट्री में फेरो अलॉय बनाने का काम होता था। मंगलवार की शाम 6 बजे ब्लास्ट की घटना हुई। फेरो एलॉयज डिवीजन में संचालित फर्नेस में लान्सिंग करने के दौरान ऑक्सीजन सिलिंडर में अचानक भीषण विस्फोट होने के कारण दुर्घटना घटित हुई।

फैक्ट्री में ब्लास्ट की घटना को लेकर मुख्यमंत्री साय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आगे भी उद्योगों में सुरक्षा पर कड़ाई से काम किया जाएगा।

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने घटना को लेकर कहा कि उरला के थ्री डी फैक्ट्री में ब्लास्ट की घटना बेहद दुखद है। फैक्ट्री को तत्काल बंद कर दिया गया है। साथ ही घटना की जांच के आदेश भी दिए गए है। उन्होंने बताया कि मृतकों 30-30 लाख मुआवजे का प्रावधान किया गया हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसपर कार्रवाई की जाएगी।

उरला स्थित थ्री डी फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में कांग्रेस ने जांच समिति का गठन कर दिया है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया को समिति का संयोजक बनाया गया है। इसमें कुल 8 सदस्य शामिल हैं। यह सभी पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। वहीं घटनास्थल का निरिक्षण कर कारणों की जांच करेंगे, जिसके बाद अपनी रिपोर्ट सौपेंगे।

कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने 3डी फैक्ट्री हादसे को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में पिछले ढाई वर्षों के दौरान औद्योगिक हादसों में 150 से अधिक मजदूरों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद सरकार प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय केवल बयानबाजी तक सीमित रही है। उन्होंने कहा कि हर बड़े हादसे के बाद मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री सख्त कार्रवाई की बात तो करते हैं, लेकिन उद्योग विभाग की ओर से नियमित निरीक्षण और सुरक्षा मानकों की प्रभावी जांच नहीं की जाती। उन्होंने मांग की कि हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक मजदूर के परिजनों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। साथ ही संबंधित फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

गनियारी पहुंचे मंत्री यादव, तीजन बाई के दशगात्र कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा

रायपुर। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव पद्म विभूषण से सम्मानित, विश्वविख्यात पंडवानी गायिका एवं छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति की अमूल्य धरोहर स्वर्गीय डॉ. तीजन बाई के गृहग्राम गनियारी स्थित निवास पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिवारजनों से भेंट कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं तथा इस दुःख की घड़ी में उन्हें ढांढस बंधाया। इस अवसर पर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार 14 जुलाई को आयोजित होने वाले दशगात्र एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में परिवारजनों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर आवश्यक व्यवस्थाओं की चर्चा की।

यादव ने कहा कि स्वर्गीय डॉ. तीजन बाई का निधन केवल उनके परिवार की नहीं, बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ और देश की सांस्कृतिक विरासत की अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपनी विलक्षण पंडवानी गायन शैली के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोककला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका सांस्कृतिक योगदान, व्यक्तित्व और कला सदैव आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि दशगात्र एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिवंगत डॉ. तीजन बाई के प्रशंसकों, कला जगत से जुड़े लोगों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति को देखते हुए बैठक, भोजन, आवागमन सहित सभी व्यवस्थाएं गरिमापूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने परिवारजनों से आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा आश्वस्त किया कि राज्य शासन इस अवसर पर हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। इस अवसर पर महापौर निर्मल कोसरे, ग्रामवासी, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

डीएमएफ से 4.13 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व तथा वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के विशेष प्रयासों से रायगढ़ जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) द्वारा 4 करोड़ 13 लाख 82 हजार 400 रुपये से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से जिले के ग्रामीण एवं खनन प्रभावित क्षेत्रों में जनसुविधाओं का विस्तार होगा और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी।

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से धरमजयगढ़ क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरघोड़ा के निर्माण एवं उन्नयन कार्य के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपये स्वीकृत किए

गए हैं। इस परियोजना के पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पांच पेयजल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। ग्राम गोरपार एवं नंदगांव में 25 केएल सम्पवेल आधारित पेयजल व्यवस्था के लिए 6 लाख 47 हजार 700 रुपये-रुपये, ग्राम शहपुर में नलकूप खनन, रॉ-वॉटर पंप एवं पाइपलाइन विस्तार के लिए 9 लाख 94 हजार रुपये, ग्राम नवापारा के लिए 5 लाख 32 हजार रुपये तथा ग्राम पुसल्दा के लिए 8 लाख 45 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन योजनाओं से संबंधित गांवों में स्वच्छ एवं नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

युवाओं को बेहतर तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए धर्मजयगढ़ स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) भवन के जीर्णोद्धार हेतु 82 लाख 86 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे संस्थान की अधोसंरचना मजबूत होगी और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

शिक्षा के क्षेत्र में भी ग्राम पंचायत साम्हारसिंघा में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण के लिए 14 लाख 30 हजार रुपये की प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की गई है। नए भवन के निर्माण से विद्यार्थियों को सुरक्षित, सुविधायुक्त और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा। स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

महादेव ऐप का संचालक सौरभ चंद्राकर ओमान में गिरफ्तार

7 साल से फरार, अब भारत लाने की तैयारी

रायपुर। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप संचालक सौरभ चंद्राकर ओमान में अरेस्ट हुआ है। उस पर फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट के जरिए ओमान में प्रवेश करने का आरोप है। चंद्राकर पिछले कुछ समय से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रह रहा था।

फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, सौरभ को भारतीय एजेंसियों द्वारा जारी इंटरपोल के रेड नोटिस के आधार पर रॉयल ओमान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने उसे वापस लाने के लिए ओमान को औपचारिक प्रत्यर्पण की तैयारियों में जुटी है। सौरभ चंद्राकर महादेव ऑनलाइन बुक मामले के प्रमुख आरोपियों में शामिल हैं ईडी ने इस मामले में अब तक 175 से ज्यादा ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किए हैं। 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 74 लोगों को आरोपी बनाया गया। साथ ही रायपुर की विशेष पीएमएलए

अदालत में 5 प्रॉसिक्यूशन शिकायतें दाखिल की गई हैं।

चंद्राकर को ओमान की राजधानी मस्कट स्थित हाई-सिक्योरिटी अल खौद डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। बता दें कि सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। वह करीब 5000 करोड़ रुपये के बेटिंग घोटाले का आरोपी है और 2019 से फरार है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट के इस्तेमाल और अवैध तरीके से ओमान में प्रवेश करने का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि उसने अपनी पैरवी के लिए मस्कट में वकीलों की एक टीम भी नियुक्त की है।

सौरभ चंद्राकर महादेव ऑनलाइन बुक मामले के प्रमुख आरोपियों में शामिल हैं। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई हजारों करोड़ रुपये के अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय लेन-देन की जांच कर रहे हैं। हाल ही में इंटरपोल की इंटरपोल की फ़ाइलों के नियंत्रण के लिए आयोग (सीसीएफ) ने चंद्राकर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी रेड नोटिस हटाने की मांग की थी।

चंद्राकर का दावा था कि भारत में उनके खिलाफ मामला राजनीतिक कारणों से दर्ज किया गया है और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। लेकिन सीसीएफ ने कहा कि मामला वित्तीय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, न कि राजनीतिक उत्पीडन् से। इसलिए रेड नोटिस जारी रहेगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सौरभ चंद्राकर ने सीसीएफ में सुनवाई के दौरान ही यूएई छोड़ दिया था। अधिकारियों का मानना है कि फर्जी पासपोर्ट के जरिए ओमान में प्रवेश करना उसकी एक सोची-समझी रणनीति हो सकती है, ताकि भारत प्रत्यर्पण प्रक्रिया में देरी हो। ओमान के कानून के तहत फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल गंभीर अपराध माना जाता है, जिसकी सजा 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकती है।

2019 से फरार चल रहे सौरभ चंद्राकर को यूएई से भारत लाने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। साल 2024 में दुबई में उसे कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया। उस समय इंटरपोल के रेड नोटिस के आधार पर यूएई अधिकारियों ने सौरभ चंद्राकर को हिरासत में लिया था और कुछ समय तक हाउस अरेस्ट में रखा था। भारत ने उसके प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भी भेजा था, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका।

कांग्रेस सरकार के संरक्षण में पल रहे घोटालेबाज अब पाताल से भी खींचे जा रहे : भाजपा

- प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजयशंकर मिश्रा ने कहा- महादेव सट्टा ऐप के मास्टरमाइण्ड की गिरफ्तारी कांग्रेस के महापाप के अंत की शुरुआत
- कका का वरदहस्त अब काम नहीं आएगा; कानून का शिकंजा कस चुका है, छत्तीसगढ़ की जनता को पाई-पाई का हिसाब देना होगा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजयशंकर मिश्रा ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइण्ड सौरभ चन्द्राकर की ओमान में हुई गिरफ्तारी के मद्देनजर तत्कालीन कांग्रेस सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय जाँच एजेंसियों की तत्परता और जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी को सट्टे के दलदल में धकेलने वाला मुख्य गुनहगार आज सलाखों के पीछे है। उसे ओमान से प्रत्यर्पित कर भारत लाया जा रहा है और अब इस 5 हजार करोड़ रुपए के महाघोटाले के असली आकाओं के चेहरे बेनकाब होकर रहेंगे।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मिश्रा ने कांग्रेस शासनकाल पर कड़ा कटाक्ष करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में भूपेश बघेल की सरकार सट्टा सरकार के रूप में याद की जाएगी। जिस भिलाई के लड़के ने 2019 से हजारों करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया, वह तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नाक के नीचे फल-फूल रहा था। क्या यह मुमकिन है कि बिना राजनीतिक संरक्षण और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के वरदहस्त के बिना इतना बड़ा सट्टा और मनी लॉन्ड्रिंग का खेल साल-दर-साल चलता रहा? छत्तीसगढ़ की जनता सब समझ रही है कि उस वक्त कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती क्यों की जा रही थी! डॉ. मिश्रा ने कहा कि जब भाजपा और केन्द्रीय एजेंसियां इस घोटाले की परतें खोल रही थीं, तब कांग्रेस के नेता इसे राजनीतिक द्वेष का नाम देकर छाती पीट रहे थे। आज जब इंटरपोल के रेड नोटिस पर ओमान पुलिस ने मास्टरमाइण्ड को दबोचा है, तो कांग्रेस के खेमे में सन्नाटा पसरा है! यह गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ के उन लाखों युवाओं के साथ न्याय की शुरुआत है, जिनका भविष्य इस सिण्डिकेट ने बर्बाद किया।

पंजाब में भी आत्मघात पर आमादा कांग्रेस

राज कुमार सिंह

'कांग्रेसी भी कांग्रेस को हराते हैं', यह कहावत जिन्हें मजाक लगती हो, उन्हें पंजाब का हाल देख लेना चाहिए। सीमावर्ती पंजाब उन चंद राज्यों में है, जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं है, पर सत्ता की दावेदार अवश्य है। 2022 में अपनी गलतियों से भी पंजाब की सत्ता गंवाने के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव में 117 में से 92 सीटें जीत कर इतिहास रचने वाली आम आदमी पार्टी (आप) कांग्रेस को टक्कर भर दे पाई। इसलिए अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता की दावेदार तो है। 18 सीटों के साथ ही सही, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। 1966 में पंजाब विभाजन के बाद के ही आंकड़े देखें तो उसके बाद हुए 13 विधानसभा चुनावों में से उसने 5 जीते हैं। ऑप्रेशन ब्ल्यू स्टार और सिख विरोधी दंगों के बावजूद पंजाब में कांग्रेस प्रासंगिकता बनाए रखने में सफल रही है। एक दल के रूप में पंजाब को सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कांग्रेस ने ही दिए हैं। कांग्रेस को शिरोमणि अकाली दल ही चुनौती देता रहा है, जिसकी सबसे बड़ी ताकत पंथक राजनीति मानी जाती है। भाजपा से दरकिनार किए गए नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस में शामिल होते ही आलाकमान उन पर इस कदर मेहरबान हुआ कि पहले तो सुनील जाखड़ को हटा कर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और फिर उनकी जिद के आगे झुकते हुए अपने सबसे वरिष्ठ नेता अमरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया। सिद्धू ने बिसात तो खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए बिछाई थी लेकिन लॉटरी चरणजीत सिंह चन्नी की खुल गई। अमरेंद्र-जाखड़ की दिग्गज जोड़ी की कांग्रेस से बेआबरू विदाई के बावजूद सिद्धू खफा ही रहे। टिकट वितरण से ले कर चुनाव प्रचार तक साफ दिखी सिद्धू और चन्नी के बीच तनातनी ने रही-सही कसर पूरी कर दी। कांग्रेस 18 सीटों पर सिमट गई और 'ट्रम्प कार्ड' बताए जा रहे दलित मुख्यमंत्री दोनों सीटों से चुनाव हार गए। चुनावी हार-जीत तो होती रहती है लेकिन कांग्रेस की समस्या है कि वह सबक नहीं सीखती। मुख्यमंत्री पद के महत्वाकांक्षी सिद्धू ने चुनाव के बाद ही कांग्रेस से दूरियां बढ़ा ली थीं लेकिन आलाकमान ने राज्य में नया नेतृत्व और मजबूत संगठन तैयार करने की दिशा में कुछ नहीं किया। 'आप' के अलावा जमीन पर कांग्रेस ही दूसरा दल रही, इसलिए लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन अच्छा रहना ही था, पर आलाकमान उसी पर आत्ममुग्ध हो गया। 'आप', अकाली दल और भाजपा की सक्रियता बढ़ती देख कांग्रेस ने भी संगठनात्मक बदलाव का संकेत तो दिया, पर दरबारी संस्कृति के वशीभूत आलाकमान साहस नहीं जुटा पाया। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग् को प्रदेश अध्यक्ष बरकरार रखते हुए चन्नी को प्रचार समिति प्रमुख और सुखजिंदर सिंह रंधावा को कोर कमेटी प्रमुख जैसे प्रयोगों द्वारा अन्य दिग्गजों को साधने की कोशिश की गई तो अंतर्कलह सतह पर आ गई। प्रदेश अध्यक्ष या फिर मुख्यमंत्री चेहरा बनने पर आमादा चन्नी ने बगावती तेवर दिखाते हुए समर्थकों की बैठक बुला ली, तो रंधावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल आए। सांसद मनीष तिवारी ने भी अपना दर्द सोशल मीडिया पर जाहिर किया। राजनीतिक विरोधी इसे चुनाव पूर्व ही टूट की संभावना के रूप में देख रहे हैं, पर कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी के विदेश यात्रा से लौटने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा लेकिन पंजाब के कांग्रेसी आत्मघात पर आमादा नजर आ रहे हैं। ज्यादा अतीत में न भी झांकें तो 2 तरह के उदाहरण हैं-राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा जैसे राज्यों में नेताओं का सत्ता संघर्ष ही कांग्रेस को ले डूबा।

भाजपा संसदीय बोर्ड : फडणवीस और योगी शामिल होंगे?

हरीश गुप्ता

नितिन नबीन के भाजपा अध्यक्ष बनने के साथ ही, 12 सदस्यीय संसदीय बोर्ड, जो कि कागजों पर सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है (जैसा कि कई लोग कहते हैं), का पुनर्गठन हो सकता है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के अलावा, प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा इसके सदस्य हैं।

साथ ही महासचिव (संगठन) बीएल संतोष भी इसके सदस्य हैं। नितिन गडकरी को कुछ अज्ञात कारणों से हटा दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्रियों बीएस येदियुरप्पा और सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद सांत्वना के तौर पर शामिल किया गया था। इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, के। लक्ष्मण और सत्यनारायण जटिया को शामिल करने का कारण भी कभी स्पष्ट नहीं किया गया।

कहा जा रहा है कि बोर्ड का पुनर्गठन किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के 16 राज्यों में सत्ता में होने के बावजूद, बोर्ड में किसी भी मौजूदा मुख्यमंत्री का नाम नहीं है - यह उस दौर से बिलकुल उलट है जब शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए बोर्ड के सदस्य थे।

ऐसी चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। फडणवीस पहले से ही भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं। पंजाब पर ध्यान केंद्रित होने के कारण कुछ बदलावों की उम्मीद है।

भाजपा के मुख्यमंत्रियों पर रखी जा रही नजर!

ऐसे समय में, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आगामी मंत्रिमंडल फेरबदल की रूपरेखा को अंतिम रूप दे रहे हैं, सत्ता के गलियारों में चर्चा चल रही है कि बदलाव केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहेंगे। भाजपा शासित कुछ राज्यों में भी नेतृत्व परिवर्तन पर सक्रिय रूप से विचार-विमर्श हो रहा है। कुछ मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार से लेकर प्रशासनिक अक्षमता तक के आरोप लगे हैं।

उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड का साया सरकार पर मंडरा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर भी तब सवाल उठने लगे जब सर्वोच्च न्यायालय ने उनसे जुड़े एक मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया। उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य के भाजपा मुख्यमंत्री, जिन्हें अप्रत्याशित रूप से ऊपर उठाया गया था, पर भी भाई-भतीजावाद और कुशासन के आरोप लगे हैं।

दिलचस्प बात यह है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने स्वयं राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाने की इच्छा व्यक्त की है। भाजपा के एक अन्य वरिष्ठ मुख्यमंत्री ने कहा था कि पार्टी द्वारा सौंपे गए किसी भी कार्यभार को स्वीकार करने से पहले वे एक अंतिम कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं। मोदी के नेतृत्व में भाजपा का कार्यकाल दर्शाता है कि कोई भी मुख्यमंत्री अपरिहार्य नहीं है।

2014 से अब तक पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कम से कम 11 भाजपा मुख्यमंत्रियों को बदला है। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा, गुजरात में विजय रूपाणी और त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देब, तीनों ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। उत्तराखंड में शायद सबसे नाटकीय बदलाव देखने को मिला।

मार्च 2021 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने चार महीने के भीतर ही इस्तीफा दे दिया और पुष्कर सिंह धामी के लिए रास्ता साफ कर दिया। अब तो धामी भी राजनीतिक जांच के दायरे में हैं। 2023 के मध्यप्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा की शानदार जीत के बाद, शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, जो अब खुद विवादों में घिरे हुए हैं।

मनोहर लाल खट्टर ने मार्च 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर नायब सिंह सैनी के लिए रास्ता बनाया और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। इससे पहले, सर्बानंद सोनोवाल ने भी असम से केंद्र में इसी तरह का बदलाव किया, जबकि आनंदीबेन पटेल और रघुबर दास को राज्यपाल के रूप में समायोजित किया गया।

जैसे-जैसे मोदी 3.0 सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, भाजपा का संदेश अपरिवर्तित बना हुआ है: कार्यकाल नहीं, बल्कि प्रदर्शन, धारणा और राजनीतिक उपयोगिता ही सत्ता में बने रहने की अवधि निर्धारित करते हैं।

क्या नवीन बाबू की उत्तराधिकारी हैं सुजाता?

ओडिशा के राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर हलचल मची हुई है कि बीजू जनता दल (बीजद) के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अपने करीबी सहयोगी की पत्नी सुजाता राउत कार्तिकेयन को अपना उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुजाता पूर्व आईएएस अधिकारी वीके पांडियन की पत्नी हैं,

जिन्हें 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले नवीन पटनायक का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। भाजपा ने यह प्रचार किया था कि नवीन पटनायक एक 'तमिल बाहरी व्यक्ति' को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना रहे हैं, जिससे बीजद को काफी राजनीतिक नुकसान हुआ था।

चुनावी हार के बाद, पांडियन राजनीतिक परिदृश्य से दूर हो गए, जबकि उनकी पत्नी सुजाता राउत कार्तिकेयन धीरे-धीरे राजनीति में उभरने लगीं। स्वयं एक पूर्व आईएएस अधिकारी, सुजाता को नवीन पटनायक सरकार की महिला सशक्तिकरण की प्रमुख पहल की परिकल्पना और कार्यान्वयन का श्रेय दिया जाता है।

बाद में उन्होंने सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया। सुजाता अब औपचारिक रूप से बीजद में शामिल हो गई हैं। वीके पांडियन चुनाव के बाद सक्रिय राजनीति से पहले ही हट चुके थे। बीजद के अंदरूनी हलकों में यह अटकलें तेज हो रही हैं कि सुजाता पार्टी का नया चेहरा बन सकती हैं और अंततः नवीन पटनायक की राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में उभर सकती हैं।

दिलचस्प यह कि हाल ही में खबरें सामने आईं कि पटनायक के भतीजे या अन्य करीबी रिश्तेदार सक्रिय राजनीति में आने के इच्छुक नहीं हैं। खबरों के अनुसार, इसी वजह से अनुभवी नेता को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी की तलाश परिवार से बाहर करनी पड़ रही है।

एक दशक से अधिक समय तक, भाजपा को उस चीज पर गर्व रहा जिसे उसके प्रतिद्वंद्वी कभी हासिल नहीं कर सके - कठोर अनुशासन। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में, गोपनीयता संस्थागत रूप ले चुकी थी। निर्णयों को कड़ी सुरक्षा में रखा जाता था, असहमति शायद ही कभी पार्टी की दीवारों से बाहर निकल पाती थी, और प्रतिकूल मीडिया कवरेज का तुरंत मुकाबला किया जाता था,

भले ही उसे पूरी तरह से रोका न जा सके। लेकिन लगता है कि स्थिति बदल रही है। हाल ही में राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली कई खबरें सार्वजनिक हुई हैं, जिससे यह अफवाह फैल रही है कि भाजपा को भी वही समस्या हो रही है जिसको लेकर उसने कभी कांग्रेस का मजाक उड़ाया था - यानी आंतरिक तोड़फोड़। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का इशारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़े भूमि विवाद, राजस्थान के सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी से संबंधित सब्सिडी विवाद और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर लगातार पड़ रहे राजनीतिक दबाव की तरफ है। उनका कहना है कि इनमें से कोई भी खबर अंदरूनी मदद के बिना सामने नहीं आ सकती थी।

मुख्यधारा के मीडिया में ऐसी खबरों के आने से इस अटकल को और बल मिला है कि पार्टी की कभी अभेद्य रही सूचना की सुरक्षा दीवार कमजोर हो रही है। ये छिटपुट सत्ता संघर्ष हैं या किसी बड़े गुटीय उथल-पुथल के शुरुआती लक्षण, यह अभी देखना बाकी है।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

अर्थात्- लावुकायन के मत में सहस्र शब्द यहाँ गौण है (यानी धपने मुख्य अर्थ हजार का वाचक न होकर अनेकार्थ वाचक है) इसी तरह -

संवत्सरो विचालित्वात्।

(6 17 138)

(निश्चित तौर पर 360 अर्थात्- संवत्सर शब्द भी विचालि दिनों के समूह का ही वाचक न होने के कारण) अनेकार्थक है। इसतरह कार्यकारणपुरस्सर सब विप्रतिपत्तियों का निरूपण कर चुकने के बाद सिद्धान्तित करते हैं कि-

अहानि वाऽभिसंख्यत्वात्।

(6 17 140)

अर्थात्- सुनिश्चित संख्याप्रदर्शन के कारण यहाँ संवत्सर शब्द एक दिन का वाचक मानना चाहिए । तात्पर्य यह हुआ कि उपर्युक्त ताण्ड्य श्रुति में जो सहस्रवर्षीय यज्ञ का विधान लिखा है वास्तव में यहाँ एक दिन को ही एक संवत्सर समझना चाहिये । इस तरह एक ही यजमान द्वारा यह यज्ञ सम्पादन किया जा सकेगा तथा आयुष्य की असम्भवता का श्राक्षेप भी समाहित हो जाएगा ।

शत, सहस्रादि शब्दों का अर्थ बहुत भी है ।

पूर्वोक्त आयुष्य विषयक प्रमाणों में (क) में मनुष्य को सहस्रायु बताया गया है और (ख) में शतायुः कहा गया है।

यदि हम यहाँ शत और सहस्र शब्द का अर्थ लौकिक रूढ़ि के अनुसार सौ और हजार करें तो वेदों पर विरुद्धार्थ-प्रतिपादन का दोष आरोपित हो जाएगा क्योंकि एक मन्त्र सहस्रायुः बताता है और दूसरा शतायुः होना ही ठहाता है! इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष में आज भी डेढ सो दो सौ वर्ष की आयु वाले बहुत से मनुष्य देखे और सुने गये हैं जैसा कि हम आगे चलकर बतलायेंगे।

क्रमशः ...

सक्सेज और शोहरत पाने के बाद भी ताउम्र बेचैन रहे गुरुदत्त

अनन्या मिश्रा

बेहतरीन फिल्मों के जरिए भारतीय सिनेमा को गुलजार करने वाले फिल्ममेकर गुरुदत्त का 09 जुलाई को जन्म हुआ था। उन्होंने जिंदगी के हर रंग देख थे और अपने करियर में कई शानदार फिल्मों का निमार्ण करने के साथ एक्टिंग का भी लोहा मनवाया था। गुरुदत्त एक काबिल-ए-तारीफ फिल्ममेकर, अभिनेता, राइटर और प्रोड्यूसर थे। सब कुछ होने के बाद भी गुरुदत्त ताउम्र बेचैन रहे।

बेंगलुरू में 09 जुलाई 1925 को गुरुदत्त का जन्म हुआ था। इनका असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह 10वीं के आगे पढ़ाई नहीं कर पाए थे। लेकिन उनको शुरू से ही संगीत और कला में काफी दिलचस्पी थी। इस कारण उनको स्कॉलरशिप मिलने के बाद उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर में एडमिशन ले लिया था। यहां पर गुरुदत्त ने डांस सीखा और कोरियोग्राफर बन गए।

भारतीय सिनेमा की मिसाल बन चुके गुरुदत्त एक ऐसे कलाकार थे, जिन्होंने न सिर्फ जीवन को सिनेमा का पर्दा समझा, बल्कि उसमें अपना सबकुछ झोंक दिया। उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। गुरुदत्त के अंदर पर्दे पर कुछ अद्भुत और अद्वितीय रचने की बेचैनी थी। वह अपने आप में सिनेमा का महाविद्यालय थे। उनकी तीन क्लासिक फिल्में प्यासा, साहिब बीवी और गुलाम और कागज के फूल को टेक्स्ट बुक का दर्जा प्राप्त है।

साल 1946 में गुरुदत्त ने प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम एक हैं से बतौर कोरियोग्राफर अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। इसके बाद उनको फिल्म में एक्टिंग करने का भी मौका मिला था। साल 1951 में देवानंद की फिल्म बाजी के सक्सेज के बाद गुरुदत्त की मुलाकात गीता दत्त से हुई। इस फिल्म के दौरान गुरु और गीता करीब आए और उन्होंने साल 1953 में शादी कर ली।

अपनी शादीशुदा जिंदगी में गुरुदत्त काफी खुश थे और करियर में भी लगातार आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान गुरुदत्त की मुलाकात वहीदा रहमान से हुई। बताया जाता है कि वहीदा और गुरुदत्त एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए। हालांकि गुरुदत्त पहले से शादीशुदा थे, ऐसे में वहीदा रहमान की वजह से गुरुदत्त और उनकी पत्नी गीता दत्त से आए दिन झगड़े होते रहते थे। साल 1975 में गुरुदत्त और गीता की शादीशुदा जिंदगी में दरार आ गई और दोनों अलग-अलग रहने लगे।

इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्में देने वाले गुरुदत्त उस दौरान दिवालिया हुए, जब उनकी फिल्म कागज के फूल फ्लॉप हो गई। फिल्म जानकारों का कहना है कि गुरु दत्त हमेशा समय से आगे सोचते थे। उस समय में उन्होंने जिस तरह की फिल्मों का निर्देशन किया और जिस क्रिएटिविटी के साथ वो आगे बढ़े ऐसा करना सिर्फ उनके लिए ही संभव था।

जहां एक ओर उनकी निजी जिंदगी में परेशानियां थीं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रोफेशनल लाइफ में भी होने वाले नुकसान से वह टूट गए थे। गुरुदत्त ने दो बार आत्महत्या करने का भी प्रयास किया था। वहीं 10 अक्तूबर 1964 को गुरुदत्त अपने बेडरूम में मृत पाए गए।

मोदी ने इंडो पैसिफिक के सारे समीकरण ही बदल दिये

नीरज कुमार दुबे

भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बदलती वैश्विक राजनीति में दोनों देश केवल पुराने मित्र नहीं, बल्कि भविष्य के रणनीतिक साझेदार भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा ने हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को नई मजबूती दी है। जकार्ता में जिस गर्मजोशी और सम्मान के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ, उसने साफ संकेत दिया कि भारत अब एशिया की राजनीति, सुरक्षा और विकास की दिशा तय करने वाली प्रमुख शक्ति बन चुका है। देखा जाये तो प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा लोकतंत्र, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित एक नए क्षेत्रीय गठबंधन की मजबूत नींव भी साबित हुई।

इंडोनेशिया की संसद में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण रहा। उन्होंने भारत और इंडोनेशिया को केवल दो देश नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से जुड़े सभ्यतागत साझेदार बताया। रामायण, महाभारत, नालंदा और प्रम्बानन मंदिर का उल्लेख करते हुए मोदी ने साफ कहा कि समुद्र ने दोनों देशों को कभी अलग नहीं किया, बल्कि यही समुद्र दोनों को जोड़ने वाला पुल बना। उनका यह संदेश केवल सांस्कृतिक संदेश नहीं था, बल्कि इंडो पैसिफिक की नई भू-रणनीतिक सोच का संकेत भी था।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में जिस दृढ़ता से कहा कि भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद के मार्ग पर चलता है, वह सीधे तौर पर उस वैश्विक शक्ति संतुलन की ओर इशारा था जहां कई ताकतें समुद्री इलाकों पर दबदबा बनाने की कोशिश कर रही हैं। मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत और इंडोनेशिया यदि साथ खड़े होते हैं तो लोकतंत्र पर दुनिया का भरोसा और मजबूत होगा। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र आज वैश्विक राजनीति का सबसे संवेदनशील केंद्र बन चुका है।

इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि दोनों देशों के बीच हुए 20 ऐतिहासिक समझौते रहे। रक्षा, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष, दुर्लभ खनिज, दूरसंचार, कृषि, स्वास्थ्य, डिजिटल ढांचा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में हुए ये समझौते आने वाले वर्षों में भारत और इंडोनेशिया की साझेदारी को नई ऊंचाई देने वाले हैं। सबसे अधिक चर्चा ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर हुए समझौतों की रही। यह हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक संतुलन को मजबूत करने वाला कदम है।

देखा जाये तो भारत द्वारा इंडोनेशिया के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित इंडोनेशिया वैश्विक समुद्री व्यापार का अहम केंद्र है। दुनिया के बड़े हिस्से का व्यापार इसी मार्ग से गुजरता है। ऐसे में भारत और इंडोनेशिया के तटरक्षक बलों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ना सीधे तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करेगा। यह साझेदारी समुद्री डकैती, अवैध गतिविधियों और किसी भी प्रकार की आक्रामक विस्तारवादी नीति के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार करेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में महा सागर दृष्टि का उल्लेख करते हुए साफ कहा कि भारत मुक्त, खुला और नियम आधारित इंडो पैसिफिक चाहता है। यह संदेश पूरी दुनिया और खासतौर पर चीन के लिए था कि भारत किसी गुट की राजनीति नहीं बल्कि संतुलित और स्थिर वैश्विक व्यवस्था का समर्थक है। आसियान की केंद्रीय भूमिका पर भारत का जोर यह भी दिखाता है कि नई दिल्ली दक्षिण पूर्व एशिया को केवल व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि रणनीतिक सहयोगी मानती है।

हम आपको बता दें कि मोदी की इस यात्रा में तकनीक और डिजिटल क्षेत्र में हुए समझौते भी बेहद महत्वपूर्ण रहे। भारत के डिजिटल सार्वजनिक ढांचे के आधार पर इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क की शुरुआत, भुगतान प्रणाली को जोड़ने की तैयारी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा स्टार्टअप सहयोग पर सहमति इस बात का संकेत है कि भारत अब तकनीकी नेतृत्व की दिशा में भी निर्णायक भूमिका निभा रहा है। भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु का परिसर इंडोनेशिया में खोलने का फैसला शिक्षा और ज्ञान कूटनीति के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।

साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने मोदी सरकार की कई योजनाओं को अपनाया है। उन्होंने हंसी मजाक में कहा कि उन्हें खुशी है कि इन योजनाओं पर किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन इस हल्के फुल्के बयान के भीतर भारत के विकास मॉडल की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता का बड़ा संदेश छिपा था। इंडोनेशिया द्वारा भारत की कृषि तकनीक, सूखी जमीन को उपजाऊ बनाने के प्रयोग और जनकल्याण योजनाओं का अध्ययन यह दिखाता है कि दुनिया अब भारत को केवल बाजार नहीं बल्कि समाधान देने वाले राष्ट्र के रूप में देख रही है।

प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण दिया जाना भी इस यात्रा की बड़ी उपलब्धि रहा। यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। मोदी ने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा लोकतांत्रिक परंपराओं तथा सभ्यतागत रिश्तों को समर्पित किया। यह सम्मान बताता है कि दुनिया में भारत की साख पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है।

साथ ही भारत और इंडोनेशिया के बीच दुर्लभ खनिज, इस्पात आपूर्ति श्रृंखला और दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों पर हुए समझौते भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी बेहद अहम हैं। आने वाले समय में प्रौद्योगिकी और रक्षा उत्पादन के लिए दुर्लभ खनिजों की भूमिका निर्णायक होगी। ऐसे में भारत का इंडोनेशिया के साथ इस क्षेत्र में साझेदारी करना दूरगामी रणनीतिक सोच का परिचायक है। देखा जाये तो भारत अब दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि वह विकास, लोकतंत्र, सुरक्षा और सांस्कृतिक शक्ति का ऐसा संगम है जो वैश्विक व्यवस्था को नई दिशा दे सकता है।

बहरहाल, मोदी सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता यही है कि उसने भारत को रक्षात्मक सोच से निकालकर निर्णायक वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में पहुंचा दिया है। कभी केवल दक्षिण एशिया तक सीमित माना जाने वाला भारत आज इंडो पैसिफिक की धुरी बन चुका है। दुनिया के बड़े राष्ट्र भारत के साथ साझेदारी को अपनी रणनीतिक आवश्यकता मान रहे हैं। इंडोनेशिया यात्रा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति आत्मविश्वास, सांस्कृतिक गौरव, सामरिक दूरदृष्टि और वैश्विक प्रभाव का नया अध्याय लिख रही है।

आज का इतिहास

1816 दक्षिण अमेरिका के संयुक्त प्रांत ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की।
1842 नोटरी स्टैम्प लॉ को मंजूरी मिली।
1850 ज़ाचरी टेलर की मृत्यु के बाद, मिलार्ड फिलमोर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने, व्हिग पार्टी के अंतिम सदस्य इस कार्यालय को संभाला।
1852 फायर ने मॉन्ट्रियल कनाडा में 1,100 निर्माण स्थलों को नष्ट कर दिया।
1868 संयुक्त राज्य संविधान के चौदहवें संशोधन को स्वीकृति दी गई।
1877 पहली विंबल्डन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।
1896 राजनेता विलियम जेनिंग्स ब्रायन ने अपने क्रॉस ऑफ़ गोल्ड स्पेकहैडोवेटिंग बाईमेटालिज़्म को बनाया, जो अमेरिकी इतिहास के सबसे महान राजनीतिक चेहरों में से एक माना जाता है।
1900 क्वीन विक्टोरिया ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान की पुष्टि करते हुए, यूनाइटेड किंगडम की संसद के एक अधिनियम को अपनी रॉयल असेंटेंट दिया।
1903 जोसेफ स्टालिन को साइबेरिया में निर्वासित किया गया था। जोसेफ स्टालिन बाद में सोवियत संघ के नेता बने।
1922 जॉनी वीस्मुल्लर ने 58.6 सेकेंड में 100 मीटर की फ्रीस्टाइल तैराई, जिससे एक विश्व तैराकी रिकॉर्ड और द वर्ल्ड बैरियर टूट गया।
1932 ब्राजील की संघीय सरकार ने साओ पाउलो राज्य को विद्रोह कर दिया था। इसने ब्राजील में संवैधानिक क्रांति की शुरुआत की।
1943 सिसिली पर संबद्ध बलों द्वारा एक शानदार हमला किया गया था। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन हस्की के नाम से जाना जाता था। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटी।
1944 अमेरिका ने सायपन की लड़ाई जीत में हासिल की।
1958 516 मीटर (1,693 फीट) ऊँचा मेगात्सुनामी, उच्चतम सदाबहार, लिटुआ खाड़ी, अलास्का, अमेरिका।
1962 पॉप कला के लिए एक प्रारंभिक क्षण में, एंडी वारहोल के कैंपबेल के सूपकैन्स प्रदर्शनी लॉस एंजिल्स में फेरस गैलरी में खोला गया।
1991 दक्षिण अफ्रीका को ओलंपिक खेलों में दोबारा भाग लेने की अनुमति मिली।
2002 इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में अफ्रीकी संघ की स्थापना। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थाबो म्बेकी इसके पहले अध्यक्ष बने।

इंडोनेशिया में 29 करोड़ मुस्लिमों के बीच शिव धाम, दीवारों पर रामायण की कहानी

अभिनय आकाश

दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश। लेकिन वहां पर मौजूद है भगवान शिव का ऐसा भव्य मंदिर जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाती है। यह सिर्फ पत्थरों से बनी इमारत नहीं है बल्कि हजार साल पुरानी उस सांस्कृतिक यात्रा की गवाही है जिसने भारत और इंडोनेशिया को आज भी एक अदृश्य धागे में बांधे रखा है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित ब्रह्मानन शिव मंदिर इन दिनों काफी चर्चाओं में है। वजह है कि भारत का इस विश्व धरोहर मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में सहयोग का फैसला करीब 10वीं शताब्दी में बना ब्रह्मानंद मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर माना जाता है। इसकी ऊंचाई शिखर शैली भारतीय मंदिर वास्तुकला की याद दिलाती है। समय, भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं ने इस धरोहर को कई बार नुकसान भी पहुंचाया है। लेकिन हर बार इसे फिर सवारने की कोशिश की हुई है। यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर है और दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे भव्य हिंदू वास्तुकला का नमूना माना जाता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच 2025 में हुए समझौते के तहत अब इस मंदिर के जीर्णोद्धार में भारत एएसआई की विशेषज्ञता देगा। तमाम सारी बातों के बीच मूल पत्थरों को जोड़कर पुनर्निर्माण की इस तकनीक को इस्तेमाल होगा। ब्रह्मानंद मंदिर का जीर्णोद्धार दोनों देशों के बीच 2000 साल पुरानी दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करेगा।

पीएम मोदी बुधवार को इंडोनेशिया के योग्याकार्ता स्थित देश के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन पहुंचे। भगवा कुर्ता, माथे पर त्रिपुंड और पारंपरिक अंदाज में मंदिर परिसर में प्रवेश करते प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें चर्चा का विषय बन गईं। उन्होंने अपने कंधे पर अलग तरह का स्टॉल भी डाल रखा था। उनके साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी मौजूद रहे। दोनों ने मंदिर के संरक्षण-जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया। पीएम ने मंदिर में दर्शन भी किए। उन्होंने मंदिर परिसर में अपने संबोधन में कहा कि मुझे किसी न किसी रूप में हमेशा भगवान शिव से जुड़ने का मौका मिला है। सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ धाम और उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाद प्रम्बानन मंदिर के विकास का मौका मिलना मेरा सौभाग्य है।

आपको बता दें कि मूल रूप से यहां पर 240 से ज्यादा मंदिर थे। समय के साथ भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों ने इसे कई बार नुकसान पहुंचाया लेकिन जो बचा है वह आज भी भव्यता के साथ खड़ा हुआ है। इसकी

तुलना इसकी तुलना अक्सर कंबोडिया के अंकोर वार्ड से की जाती है। लेकिन ब्रह्मानंद पूरी तरह से हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है। कंबोडिया का मंदिर भी वो बड़ा विशाल है। बड़ा चर्चाओं में है। कहा जाता है कि हजारों की संख्या में जो वहां पर शिव के मूर्तियां हैं, शिवलिंग हैं, वो रावण ने बनाई थी। उसकी चर्चा फिर कभी लेकिन फिलहाल यह इंडोनेशिया के मंदिर हैं। एक नहीं 10,000 मंदिर यहां पर हैं। इन 10,000 मंदिरों का भारतीय संस्कृति से गहरा नाता है। इंडोनेशिया नौसेना का आधिकारिक आदर्श वाक्य ज्वेल जयामहे संस्कृत में वहीं राष्ट्रीय नारा है भिन्नका तंगुल ईका जापानी ग्रंथ काकाबिन समसेतु में किया गया है जिसमें संस्कृत के कई शब्द हैं इंडोनेशिया के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर भी छपी हुई है जहां पर गणेश का ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक माना माना जाता है। जकार्ता के बीचों-बीच 85 फीट ऊंची अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ की प्रतिमा भी लगी हुई है जो शहर के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश होने के बावजूद इंडोनेशिया में आज भी रामायण का मंचन होता है। इसे देखने के लिए हर साल यहां पर लाखों पर्यटक पहुंचते हैं। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय एयरलाइन गरुड़ इंडोनेशिया का नाम भी गरुड़ के नाम पर रखा गया है। जिसका उल्लेख भारतीय शास्त्रों में, भारतीय वेदों में और भारतीय ग्रंथों में है।

अगर कोई आपसे पूछे कि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर कौन सा है? तो जवाब होगा ब्रह्मानंद मंदिर। लेकिन इसकी पहचान सिर्फ इसके आकार से नहीं बल्कि उस अद्भुत कला और इतिहास से है जिसने इसे विश्व धरोहर बना दिया है। करीब 1100 साल पहले जावा की धरती पर ऐसा मंदिर परिसर बनाया गया जिसने भारतीय स्थापत्य कला को स्थानीय परंपराओं के साथ जोड़ा और एक नई पहचान दी। मंदिर का सबसे ऊंचा शिखर भगवान शिव को अर्पित है। समर्पित है और इसकी ऊंचाई लगभग 47 मीटर मानी जाती है। दूर से देखने पर लगता है कि मानो पत्थर का कोई पर्वत आसमान को छू रहा हो। जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वही है ब्रह्मानंद परिसर और मंदिर। ब्रह्मानंद परिसर में कुल सैकड़ों छोटे-छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। इनके प्रमुख तीन मंदिर हैं। भगवान शिव का मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर, भगवान ब्रह्मा का मंदिर यह समर्पित मंदिर हैं। इनके सामने नंदी भी हैं, गरुड़ भी हैं और हंस के मंदिर भी बने हुए हैं। मंदिर की दीवारों पर रामायण और कृष्ण कथा की नक्काशी भारतीय संस्कृति के गहरे रिश्ते और प्रभाव को दिखाती है।

पूरे इंडोनेशिया में 10,000 हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी का देश और उस देश में 10,000 हिंदू मंदिर मानते हैं ना भारतीय संस्कृति को। अब जरा इसकी तमाम जो खासियत हैं उनका जिक्र मैं कर लेता हूं। असल में ब्रह्मानंद मंदिर उसकी जो परिसर है त्रिमूर्ति की पूजा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मुख्य और सबसे बड़ा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसके दाई ओर भगवान विष्णु और बाई ओर ब्रह्मा जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। मुख्य मंदिरों के सामने देवी देवताओं के वाहन भी बने हुए हैं। जिसमें शिव के वाहन नंदी बैल का मंदिर सबसे प्रमुख है। मंदिर की जो लंबी गैलरियों की दीवारों पर रामायण और भागवत पुराण की कथाएं लिखी हुई हैं। नक्काशी के तौर पर उकेरी गई हैं जो देखने वालों को प्राचीन काल में ली जाती हैं। और यह मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है बल्कि हिंदू पुराणों का जीवंत संग्रहालय भी बना हुआ है।

भारत के सहयोग से चलाया जा रहा यह संरक्षण और बहाली प्रोजेक्ट, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में साझा सभ्यतागत विरासत को बचाने की नई दिल्ली की कोशिशों में एक और अहम पड़ाव है। यह पहल भारत की %एक्ट ईस्ट पॉलिसी% और सांस्कृतिक कूटनीति के अनुरूप है; यह एशिया के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू स्मारकों में से एक की सुरक्षा करते हुए इंडोनेशिया के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करती है।

पश्चिम एशिया में भारत के नए रक्षा समीकरण

अरुणिम भूयान

मिस्र के नए सामरिक कमान मुख्यालय, जिसे द ऑक्टागन कहा जाता है, का उद्घाटन पहली नजर में एक घरेलू सैन्य बुनियादी ढांचा परियोजना लग सकता है। हालांकि, भारत के लिए इस विशाल कमान परिसर का महत्व मिस्र की सीमाओं से कहीं आगे तक जाता है। जैसे-जैसे नई दिल्ली अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के पश्चिमी पूरक और महासागर विजन के तहत पश्चिमी एशिया के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत कर रहा है, वैसे-वैसे सैन्य रूप से आधुनिक होता मिस्र समुद्री सुरक्षा की रक्षा करने, महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों की स्थिरता सुनिश्चित करने और मध्य पूर्व व उत्तरी अफ्रीका में उभरते भू-राजनीतिक संतुलन को आकार देने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात की समाचार वेबसाइट द नेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, फील्ड मार्शल की वर्दी और काले चश्मे में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी, जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी हैं, ने नए सामरिक कमान मुख्यालय के उद्घाटन का उपयोग अपने 13 साल के राष्ट्रपति कार्यकाल के मुख्य स्तंभों को फिर से दोहराने के लिए किया। अपने संबोधन में उन्होंने राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ सरकार के कड़े रुख, अरब स्प्रिंग विद्रोहों को खारिज करने और एक मजबूत राज्य के माध्यम से स्थिरता बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। मिस्र को एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में रेखांकित करते हुए, सिसी ने कहा कि क्षेत्रीय मामलों को संभालने में देश का अनुभव बेजोड़ है। उन्होंने इजरायल के साथ मिस्र की ऐतिहासिक 1979 की शांति संधि का ज़िक्र किया और इसे मध्य पूर्व में स्थिरता की आधारशिला बताया, जो आज भी क्षेत्रीय सुरक्षा को तय करती है। राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय संघर्षों को सुलझाने में मिस्र की राजनयिक भूमिका पर भी ज़ोर दिया। तुर्की और कतर के साथ मिलकर, काहिरा ने अक्टूबर 2025 में हुए उस युद्धविराम की मध्यस्थता में मुख्य भूमिका निभाई थी जिसने गाजा में दो साल से चल रहे संघर्ष को रोका था। इसके अलावा, मिस्र ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से एक राजनयिक रोडमैप तैयार करने में भी शामिल था। देश के लिए अपने दृष्टिकोण को फिर से दोहराते हुए, सिसी ने संकल्प लिया कि मिस्र मौजूदा चुनौतियों के बावजूद राष्ट्र-निर्माण और आर्थिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना जारी रखेगा। नागरिकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन स्तर में सुधार करना और मिस्रवासियों पर आर्थिक बोझ को कम करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और नीति निर्धारण में एक मुख्य विचार बना हुआ है। द ऑक्टागन का उद्घाटन मिस्र की उस महत्वाकांक्षा को दर्शाता है जिसके तहत वह एक तकनीकी रूप से उन्नत क्षेत्रीय सैन्य शक्ति के रूप में उभरना चाहता है, जो उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी भूमध्य सागर, लाल सागर और व्यापक मध्य पूर्व में सैन्य अभियानों का समन्वय करने में सक्षम हो। भारत के लिए इस घटनाक्रम के महत्वपूर्ण रणनीतिक मायने हैं क्योंकि मिस्र अपनी व्यापक भारत-प्रशांत और ग्लोबल साउथ नीतियों के तहत पश्चिम एशिया के साथ नई दिल्ली के उभरते संबंधों में एक केंद्रीय स्थान रखता है। मिस्र स्वेज नहर को नियंत्रित करता है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर और हिंद महासागर से जोड़ने वाला दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है। वैश्विक व्यापार का लगभग 12-15 प्रतिशत हिस्सा और यूरोप के साथ भारत के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी नहर (स्वेज नहर) से होकर गुजरता है। इसलिए, मिस्र की सैन्य कमान और समुद्री सुरक्षा क्षमताओं में कोई भी सुधार इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की सुरक्षा को सीधे प्रभावित करता है। द ऑक्टागन की स्थापना उन्नत कमान-और-नियंत्रण प्रणाली (कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्षमताओं और संयुक्त सैन्य योजना को एक कमान के तहत जोड़ने के मिस्र के प्रयासों को दर्शाती है। यह समुद्री सुरक्षा खतरों से लेकर आतंकवाद और पड़ोसी देशों में संघर्षों जैसी क्षेत्रीय चुनौतियों का तेजी से जवाब देने की काहिरा की क्षमता को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काहिरा की राजकीय यात्रा के बाद 2023 में भारत और मिस्र ने अपने संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाया था। यह रिश्ता अब पारंपरिक राजनीतिक जुड़ाव से आगे बढ़कर रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, साइबर सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और अंतरिक्ष सहयोग तक फैल गया है।

मायावती की जमीन पर अखिलेश यादव की एंट्री

नीरज कुमार दुबे

उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों समाजवादी पार्टी ने ऐसा दांव चला है, जिसने बहुजन समाज पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी है और भारतीय जनता पार्टी को भी माथा खुजलाने पर मजबूर कर दिया है। बात सिर्फ टिकट बांटने की नहीं है, बल्कि उस नई सामाजिक बिसात की है, जिस पर अखिलेश यादव अब दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समीकरण को नए अंदाज में जमाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रचारअभियान और चुनाव

हम आपको बता दें कि सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है कि समाजवादी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में लगभग सौ दलित उम्मीदवार मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। इनमें सामान्य सीटों पर भी दलित चेहरों को मौका देने की रणनीति शामिल है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि अगर बहुजन समाज पार्टी की पारंपरिक जमीन पर सेंध लगानी है तो केवल भाषणों से काम नहीं चलेगा, बल्कि टिकट वितरण में भी साहस दिखाना होगा।

दरअसल, यह पूरी कवायद उस बदले हुए राजनीतिक माहौल का नतीजा है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे अपने पुराने प्रभाव से दूर होती दिखाई दे रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुला और उसका मत प्रतिशत भी तेजी से नीचे आया। उधर समाजवादी पार्टी ने यह समझ लिया है कि अगर दलित मतदाता का एक हिस्सा भी उसके साथ मजबूती से आ गया, तो उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता और आसान हो सकता है।

इसी सोच के तहत पार्टी अब आरक्षित सीटों तक सीमित रहने की बजाय सामान्य सीटों पर भी दलित प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जहां समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत नहीं है, वहां दलित उम्मीदवारों को

उतारकर नया सामाजिक समीकरण बनाया जाएगा। यानी जहां जमीन कमजोर है, वहां जातीय गणित से जीत का पुल तैयार करने की कोशिश होगी। राजनीति

दिलचस्प बात यह है कि यह प्रयोग पूरी तरह नया भी नहीं है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कई दलित उम्मीदवार उतारे थे और उसका फायदा भी मिला। अयोध्या, मेरठ और फैजाबाद जैसी सीटों पर पार्टी ने दलित चेहरों को मौका देकर राजनीतिक संदेश दिया था कि अब पार्टी केवल यादव मुस्लिम पहचान तक सीमित नहीं रहना चाहती। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव अब उस छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी को केवल यादव और मुस्लिम मतों की पार्टी माना जाता था। यही कारण है कि पार्टी अब दलित समाज में लगातार संवाद बढ़ा रही है। पंचायत स्तर से लेकर विधान परिषद तक प्रतिनिधित्व का नया खाका तैयार किया जा रहा है।

समाजवादी पार्टी के भीतर भी यह समझ बन रही है कि बहुजन समाज पार्टी के कमजोर पड़ने से जो राजनीतिक खालीपन बना है, उसे भरने का यह सबसे सही समय है। पार्टी नेताओं का दावा है कि दलित समाज का एक हिस्सा अब नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में है। ऐसे में अगर सम्मानजनक भागीदारी दी जाए, तो यह वर्ग स्थायी रूप से नए गठजोड़ की तरफ आ सकता है।

उधर, भारतीय जनता पार्टी भी इस बदलते समीकरण को लेकर सतर्क दिखाई दे रही है। भाजपा को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित मतदाता सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि चुनावी दिशा तय करने वाला निर्णायक वर्ग है। इसी कारण भाजपा लगातार अपने दलित संपर्क अभियान को तेज कर रही है और यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसका सामाजिक विस्तार अभी भी कायम है।

बहुजन समाज पार्टी के लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है। कभी दलित राजनीति की सबसे बड़ी धुरी रही पार्टी अब दो तरफा दबाव में है। एक तरफ भाजपा उसका परंपरागत वोट बैंक खींच रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी नए अंदाज में दलित नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

राजनीति के पुराने खिलाड़ी मानते हैं कि यह पूरा खेल केवल टिकटों का नहीं, बल्कि प्रतीकों और संदेशों का है। अखिलेश यादव यह जताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी अब केवल एक जाति विशेष की पार्टी नहीं रही। वहीं भाजपा यह साबित करने में जुटी है कि उसका सामाजिक समीकरण अभी भी सबसे व्यापक है। और बहुजन समाज पार्टी इस कोशिश में लगी है कि उसका कोर मतदाता पूरी तरह छिटकने न पाए।

बहरहाल, उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह नया दौर बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब चुनावी मंचों पर केवल विकास और वादों की बात नहीं होगी, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व की नई पटकथा भी लिखी जाएगी। फिलहाल इतना तय है कि दलित राजनीति अब केवल एक पार्टी की जागीर नहीं रही। साइकिल, कमल और हाथी तीनों अब उसी मैदान में उतर चुके हैं, जहां हर वोट के पीछे पूरा सामाजिक गणित छिपा है।

बांग्लादेश-चीन की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी

आनंद कुमार

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन की हालिया यात्रा दक्षिण एशिया की बदलती भू-राजनीति का एक महत्वपूर्ण संकेत है। इस यात्रा को केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता कि उन्होंने नई दिल्ली से पहले बीजिंग का दौरा किया, बल्कि इसलिए कि, इस दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को एक नए रणनीतिक स्तर पर पहुंचाने का निर्णय लिया। रणनीतिक हलकों में इसे दिल्ली-ढाका रिश्तों में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।

चीन और बांग्लादेश ने अपने व्यापक रणनीतिक सहयोगी संबंधों को और मजबूत करते हुए 'नए युग में साझा भविष्य वाले चीन-बांग्लादेश समुदाय' के निर्माण की घोषणा की। दोनों देशों ने कूटनीति, रक्षा, व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे, जल संसाधन, संपर्क, शिक्षा और बहुपक्षीय सहयोग सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। यह घटनाक्रम भारत के लिए स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय तो है ही, लेकिन अपनी पड़ोस नीति की समीक्षा करने और उससे जुड़े कई प्रश्नों का उत्तर खोजने का अवसर भी है। यात्रा के दौरान हुए समझौतों में सबसे अधिक ध्यान दो परियोजनाओं ने आकर्षित किया।

पहली, तीस्ता नदी समग्र प्रबंधन एवं पुनर्स्थापन परियोजना (टीआरसीएमआरपी), जिसके लिए चीन ने तकनीकी सहयोग और व्यवहार्यता अध्ययन में सहायता देने का आश्वासन दिया है। दूसरी, मोंगला बंदरगाह के आधुनिकीकरण और उसके निकट चीनी आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्र के विकास की परियोजना। दोनों परियोजनाएं भारत की पूर्वी सीमा के निकट स्थित हैं। तीस्ता परियोजना भारत के लिए इसलिए संवेदनशील है, क्योंकि यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट है, जो पूर्वोत्तर भारत को देश के शेष भाग से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण जीवनरेखा है। वहीं मोंगला बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जहां चीन पिछले कुछ वर्षों से अपनी आर्थिक व सामरिक उपस्थिति बढ़ा रहा है। इसलिए, भारत की चिंता स्वाभाविक है। दरअसल, चीन का बांग्लादेश में प्रभाव अचानक नहीं बढ़ा है। पिछले दो दशकों

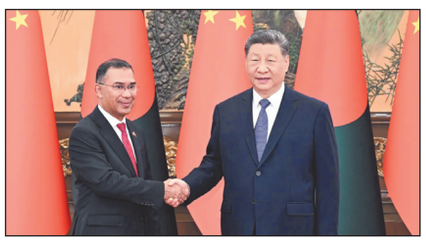

में उसने योजनाबद्ध तरीके से बांग्लादेश में अनेक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश किया है। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, रक्षा उपकरणों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता व बड़े विकास साझेदारों में शामिल है। इसलिए, यह यात्रा नए दौर की शुरुआत कम, पहले से चल रही प्रक्रिया के और ज्यादा संस्थागत तथा व्यापक होने का संकेत अधिक है।

यह समझना जरूरी है कि बांग्लादेश ने चीन का साथ सिर्फ अधिक पैसे की वजह से नहीं चुना, बल्कि इसलिए भी, क्योंकि चीन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करता है। इस संदर्भ में भारत का रिकॉर्ड मिश्रित रहा है। मोंगला बंदरगाह इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। 2015 में बांग्लादेश ने इस बंदरगाह के निकट विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने के लिए भारत को भूमि आवंटित की थी। भारत ने परियोजना स्वीकार भी कर ली, पर वर्षों तक कार्य शुरू नहीं हो सका। अंततः बांग्लादेश ने परियोजना चीन को सौंप दी। इसी प्रकार, तीस्ता जल बंटवारा समझौता भी एक दशक से अधिक समय से लंबित है। पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध के कारण इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इसलिए, बांग्लादेश ने नदी प्रबंधन के लिए चीन की ओर देखना शुरू किया। यहीं भारत को आत्ममंथन करने की जरूरत है। चीन ने दक्षिण एशिया में अनेक परियोजनाओं को केवल व्यावसायिक दृष्टि से नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा है। जबकि, भारत कई बार प्रशासनिक प्रक्रियाओं, वित्तीय बाधाओं व घरेलू राजनीतिक कारणों से समय पर निर्णय नहीं ले पाया। नतीजतन, जिन परियोजनाओं को भारत अपने प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा मानता था, वे चीन के हाथों में चली गईं।

इस यात्रा की खास बात यह रही कि दोनों देशों के रिश्ते अब सिर्फ आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रहे, बल्कि रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। फिर भी, यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि बांग्लादेश भारत से दूर जा रहा है। आज वैश्विक राजनीति में अधिकांश मध्यम व छोटे देश किसी एक शक्ति के साथ पूर्ण रूप से जुड़ने के बजाय बहु-संरेखण की नीति अपना रहे हैं। वे अपने राष्ट्रीय हितों को अधिकतम करने के लिए विभिन्न शक्तियों के साथ समानांतर संबंध विकसित कर रहे हैं। भारत भी अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और यहां तक कि चीन के साथ भी सहयोग बनाए रखता है। ऐसे में, यदि बांग्लादेश चीन और भारत, दोनों के साथ संबंध मजबूत रखना चाहता है, तो इसे असामान्य नहीं माना जाना चाहिए।

वास्तव में, भारत और बांग्लादेश के संबंधों की बुनियाद इतनी मजबूत है कि उन्हें आसानी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। करीब चार हजार किलोमीटर लंबी साझा सीमा, साझा नदियां, व्यापक व्यापार, ऊर्जा सहयोग, सीमा पार संपर्क, सांस्कृतिक निकटता और लोगों के बीच गहरे संबंध दोनों देशों को स्वाभाविक साझेदार बनाते हैं। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों देशों ने हाल के महीनों में संबंध सुधारने की दिशा में कुछ सकारात्मक कदम भी उठाए हैं। भारत ने ऊर्जा संकट के समय बांग्लादेश को ईंधन की आपूर्ति भी की है। स्पष्ट है कि दोनों संबंधों को पूरी तरह खराब नहीं होने देना चाहते। भारत के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि पड़ोस नीति केवल ऐतिहासिक संबंधों या भौगोलिक निकटता के भरोसे सफल नहीं हो सकती। प्रभाव बनाए रखने के लिए समय पर परियोजनाएं पूरी करनी होंगी, विकास साझेदारी को अधिक विश्वसनीय बनाना होगा और पड़ोसी देशों की प्राथमिकताओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा। भारत की सुरक्षा चिंताएं भी पूरी तरह उचित हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या बंगाल की खाड़ी के निकट चीन की बढ़ती उपस्थिति का सामरिक महत्व है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। पर, इन चिंताओं का समाधान केवल विरोध दर्ज कराने या बांग्लादेश के निर्णयों पर असंतोष व्यक्त करने से नहीं होगा। भारत को स्वयं को सक्षम, भरोसेमंद और त्वरित विकास साझेदार के रूप में पेश करना होगा।

प्रधानमंत्री बदले, लेकिन नहीं बदला ब्रिटेन के मशहूर बिल्ले का पता

क्षमा शर्मा

पिछले दिनों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एक एक्स अकाउंट से ट्वीट किया गया कि मैंने स्टार्मर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। यह ट्वीट किसी इन्सान के नहीं, बल्कि एक बिल्ले के अकाउंट से किया गया था। इन महाशय का नाम लैरी द कैट है। यह प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट का स्थायी निवासी है।

बताया जाता है कि 2011 में जन्मे इन महाशय को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कैमरून के कार्यकाल में पशुओं के अनाथालय से लाया गया था। कैमरून इसे अपने बच्चों के लिए लाए थे। हालांकि, कैमरून के बारे में कहा जाता है कि उन्हें बिल्लियां पसंद नहीं थीं, लेकिन इस बिल्ले ने उनके दिल में जगह बनाई। जब वह जाने लगे, तो इसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर नहीं ले जा सके, क्योंकि यह उस जगह का स्थायी निवासी है। वह बहुत उदास भी हुए। लैरी को भी उनसे और परिवार से बहुत लगाव था। इसलिए, सोचा जा रहा था कि उनके जाने के बाद पता नहीं यह कैसे रहेगा। लेकिन, इसने यह स्थान नहीं छोड़ा। कैमरून के बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए, सबके दिलों में लैरी ने अपनी जगह बनाई। बिल्लियों के बारे में कहा जाता है कि वे घर बदलती रहती हैं, लेकिन लैरी शायद स्थान प्रिय है। इसलिए, वह कहीं नहीं गया। वह अब तक छह प्रधानमंत्रियों-डेविड कैमरून, टेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक और कीर स्टार्मर-के कार्यकाल को देख चुका है। कई लोग मजाक में कहते हैं कि लैरी अकेला, इन सभी प्रधानमंत्रियों से अधिक होशियार है। स्टार्मर से जब नाटो प्रमुख मार्क रुटे मिलने आए थे, तो जाते वक्त उन्होंने भी इससे प्यार से बातचीत की थी।

लैरी सिर्फ प्रधानमंत्री आवास का निवासी ही नहीं सरकारी अधिकारी भी है। इसे चीफ माउजर आफ कैबिनेट ऑफिस का पद मिला हुआ है। इसका काम है, सरकारी इमारतों में चूहों से निपटना। इसके अलावा, परिसर की सुरक्षा और वहां आने वाले महत्वपूर्ण लोगों का अभिवादन और स्वागत करना। यह अक्सर पुराने फर्नीचर पर लेटकर झपकी लेता दिखाई देता है। यहां तक कि पत्रकार वार्ताओं के समय भी सो जाता है। विश्व के बड़े-बड़े लोगों से मिलता है, पर उन्हें जरा भी भाव नहीं देता।

ब्रिटेन की मीडिया का एक हिस्सा लैरी को आलसी कहता है, क्योंकि अभी तक महज दो चूहों के शिकार का काम ही इसके नाम दर्ज है। यह प्रधानमंत्री आवास में सबसे अधिक दिन

काम करने वाला पालतू जानवर भी है। यह ब्रिटेन के मीडिया में छाया रहता है और सोशल मीडिया का स्टार है। इसके सोशल मीडिया अकाउंट से अक्सर ऐसे संदेश आते हैं, जिन्हें पढ़कर लोग हंसते हैं और आनंदित होते हैं। जब इसे प्रधानमंत्री आवास में लाया गया था, तो कुछ ही घंटों में यह ग्लोबल आइकन बन गया था। दुनियाभर में इसके लाखों फॉलोअर्स हैं।

प्रधानमंत्री आवास में बिताए गए इसके पहले सौ दिन पर एक पिक्चर बुक भी मिलती है। इसे जेम्स रॉबिन्सन ने लिखा है। लैरी की एक आत्मकथा भी है। बच्चों के लिए भी बहुत-सी रंग-बिरंगी किताबें हैं, जिनका प्रमुख नायक लैरी ही है। ये इतनी दिलचस्प हैं कि बच्चे बड़ी संख्या में इन्हें खरीदते और बड़े चाव से पढ़ते हैं। भारतीय मुद्रा में इनकी कीमत एक सौ पचास रुपये से लेकर छह सौ रुपये तक है। लैरी के बारे में यहां तक कहा जाता है कि वह प्रेस फोटोग्राफर्स और मीडिया को लेकर बहुत सजग है। इसीलिए, उसकी तरह-तरह की फोटोज दिखाई देती हैं। मजाक में लैरी के बारे में यह भी मशहूर है कि वह एक किताब लिख रहा है-द राइज एंड फाल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, क्योंकि लैरी ने छह प्रधानमंत्रियों को आते-जाते देखा है।

अब इसकी उम्र हो चली है, मगर रिटायर होने को तैयार नहीं। हालांकि, जब यह इस दुनिया से विदा होगा, इसके लिए भी सरकार की तरफ से मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स को शामिल करने के लिए योजना तैयार है। प्रेस रिलीज से लेकर सोशल मीडिया पर सूचना और बहुत-से चित्र। इन सभी को एक कंप्यूटर में रखा गया है। चूंकि, लोग इसकी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं, इससे लगाव भी है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी मृत्यु पर राष्ट्रीय सम्मान देने की बात भी हो रही है।

इसके बाद भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कोई बिल्ला या बिल्ली आएगी, यह तो समय ही बताएगा। सफेद, काले इस बिल्ले के भाग्य जैसा भाग्य आखिर दुनिया में कितनी बिल्लियों को नसीब होता है। फिलहाल तो, लैरी, तुम जियो हजारों साल।

जानकारी

नीम के तेल में छिपा है हर रोग का उपचार

नीम की प्रयोग आयुर्वेदिक औषधि के रूप में किया जाता है। नीम के बीज से निकाला हुआ तेल हमारे कई काम आ सकता है। नीम के तेल में बहुत सारे औषधीय गुण छुपे हुए हैं। यह तेल बेहद ही सुगंध वाला होता है। ये सेहत और सौंदर्य दोनों के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा यह कई बीमारियों के लिए भी कारगर होता है। इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

मोतियाबिंद की बीमारी: आंखों में मोतियाबिंद और रतौंधी हो जाने पर नीम के तेल को सलाई से आंखों में अंजन की तरह से लगाएं। आंखों में सूजन हो जाने पर नीम के पत्ते को पीस कर अगर दाई आंख में है तो बाएं पैर के अंगूठे पर नीम की पत्ती को पीस कर लेप करें। ऐसा अगर बाई आंख में हो तो दाएं अंगूठे पर लेप करें, आंखों की लाली व सूजन ठीक हो जाएगी।

मलेरिया से बचाव: नीम से मलेरिया भगाया जा सकता है। इससे मच्छर और पैदा होने वाले लार्वा को खत्म किया जा सकता है। मच्छरों पर यह बहुत असरदार होता है। नीम के तेल से मलेरिया पर काबू पाया जा सकता है। किसानों के लिए यह जैविक कीटनाशक का काम करता है। यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। यह जमीन या पानी की आपूर्ति में कोई हानिकारक पदार्थ नहीं मिलाता, यह बायोडीग्रेडेबल है। यह मधुमक्खियों और केंचुए के रूप में उपयोगी कीड़े को नुकसान नहीं पहुंचाता।

स्वस्थ त्वचा: रूखी सूखी त्वचा के लिए नीम बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। एक्जिमा से स्किन पर सूजन और खुजली होती है। इसके लिए इफेक्टिड एरिया में नीम का तेल लगाएं। जलने की वजह से शरीर में जख्म बन जाने पर नीम का तेल लगाने से जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। इन्फेक्शन से बचाता है। कील-मुंहासों और त्वचा के दाग भी दूर हो जाते है।

रक्तप्रदर मे लाभ: आधा चम्मच नीम का तेल दूध में मिलाकर सुबह-शाम को पीने से रक्तप्रदर और सभी प्रकार के प्रदर बन्द हो जाता है। एथलीट फूट, नाखून कवक जैसे त्वचा रोग फंगल संक्रमण के कारण होते हैं। नीम में पाए जाने वाले दो योगिक 'गेदुनिन' और 'निबिडोल' त्वचा में पाए जाने वाले फफूंद को समाप्त करते हैं और संक्रमण को कम करते हैं।

रुसी दूर करे: बालों को चमकदार, स्वस्थ बाल के लिए,सूखापन दूर करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग करें। नीम का तेल नियमित लगाने से सिर की खुजली दूर होगी जिससे रूसी की समस्या ठीक हो जाएगी। इसके तेल से बाल दो मुंहे भी नहीं होते।गंजेपन की समस्या है तो सिर में नीम का तेल लगाएं। इससे जूएं-लीखें भी दूर हो जाती हैं।

दांतों और मसूड़ों की मजबूती: दांतों और मसूड़ों की समस्या में नीम का तेल की कुछ बूंदों मंजन में मिला कर मले। नीम के तेल में एंटी बेक्टीरियन तत्व पाए जाते हैं । जो दांतों में होने वाली समस्यओं जैसे दांतों के दर्द, दांतों का कैंसर, दांतों में सड़न आदि में राहत देता है।

रोके बढ़ती हुई उम्र: नीम में पाये जाने वाले तत्व ऑक्सीकरण रोधक होते हैं। जो चेहरे में होने वाले परिवर्तनों को रोक देते हैं। नीम के तेल लगाने से चेहरे की झुर्रियां कम होती है। और आपकी बढ़ती हुई उम्र रूक जाती है।

गर्मी और बारिश में सफर
खूबसूरत भी है खतरनाक भी

इन बातों का रखें ख्याल तो होगी आसानी

गर्मियों की छुट्टियां खत्म होते होते मानसून शुरू हो जाता है। अक्सर लोग इन्हीं दिनों सफर के लिए जाते हैं। ऐसे में इन बातों का रखें खास ध्यान।

हर मौसम में रखें ख्याल

इन दोनों ही मौसम में आप सफर पर सूती और ढीले ढाले कपड़े लेकर जायें। ये कपड़े जल्दी सूखने वाले और ईको फ्रेंडली हो तो और भी अच्छा है। इसी तरह सबसे आरामदेह फुटवियर को सफर के लिए रखें। इसके अलावा सनग्लास और सनस्क्रीन ले जाना बिलकुल ना भूलें।

स्ट्रीट फूड को विशेष तौर पर अवॉइड करें। इससे गैस, अपच और डिहाइड्रेशन जैसी प्राब्लम्स हो सकती हैं। ज्यादा ऑयली खाना खाने से भी बचें। ठंडे और लिक्वेड फूड जूस, तरबूज खाना प्रिफर करें।

अगर आप को कोई स्पेसफिक प्राब्लम है और उसकी दवायें खाते हैं तो उसे जरूर साथ रख लें। गर्भवती महिलायें पानी और स्नैक्स जरूर साथ में कैरी करें ताकि लंबे सफर के दौरान बीच बीच में कुछ खाती और पीती रहें। बच्चों के लिए भी सफर में कुछ खाने पीने लेकर जरूर चलें। सरदर्द, अपच, उल्टी रोकने वाली जरूरी दवायें और ओरल रिहाइड्रेशन पाउडर आदि ले जाना ना भूलें।

सफर चाहे कार, विमान, ट्रेन या बस किसी से भी करें पर सबसे कंफर्टेबल तकिया जरूर कैरी करें ताकि बैकपेन जैसी प्रॉब्लम्स ना हों। साथ ही थकान से बचने के लिए बीच-बीच में रुक कर थोड़ा आराम जरूर करें।

मानसून में कार के सफर में रखें याद

अगर आप बाई रोड कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आप सड़क के लगभग बीच में ही गाड़ी चलायें। हालाकि कई बार भारी ट्रैफिक के दौरान यह संभव नहीं होता है लेकिन कोशिश करें आप सड़क के ज?यादा किनारे न जायें।

अक्सर लांग ड्राइव पर ब्रेक का प्रयोग कम होता है लेकिन बीच-बीच में हल्का सा ब्रेक लगाते रहें इससे ब्रेकिंग पैड सुखते रहेंगे और अचानक जरूरत पड़ने पर उनकी ग्रिप अच्छी रहेगी।

गाड़ी में म्यूजिक सुनना सबको पसंद होता है पर वाल्यूम को धीमा रखें जिससे कार पर पड़ने वाली बारिश की बूंदों की आवाज से आपको बारिश की गति का अंदाजा मिलता रहेगा।

बरसात में ड्राविंग के दौरान सड़क पर बड़े वाहन जैसे बस, ट्रक आदि से दूरी बनाये रखें और उन्हें ओवरटेक करने की गलती ना करें।

सड़क के किनारे मिट्टी वाले रास्ते से बचें। बारीश के बाद मिट्टी पर फिसलन बढ़ जाती है जो गति और ब्रेकिंग सिस्टम दोनों को प्रभावित कर नुकसान पहुंचा सकती है।

बनें टेक्नोफ्रेंडली

यात्रा के लिए मौसम कोई भी हो पर बड़े काम की बात है। आज कल स्मार्ट फोन्स और टैक्नॉलिजी का जमाना है। इसलिए सफर पर जाने के पहले कई सिक्योरिटी एप्स को अपने फोन में डाऊनलोड करके रखें। ये आपके लिए खासी मददगार साबित हो सकती हैं।

इन एप्स से आपको जहां आप घूमने जा रहे हैं उसके नक्शे, होटल से लेकर फ्लाइट्स या दूसरे सफर के साधनों और लेंग्वेज ट्रांसलेटर्स तक हर चीज में मदद कर सकती हैं।

सबसे आखिर में रवाना होने से पहले जिस जगह आप जा रहे हैं वहां की टूरिज्म वेबसाइट्स पर नजर डाल लें और समझ लें कि आपने सफर के लिए सही मौसम चुना है।

र्यूमैटॉइड अर्थराइटिस

जब खुद का दुश्मन बने शरीर...

रीढ़ की हड्डी (स्पाइन) को कई विकारों से ग्रस्त कर देता है स्पाइनल र्यूमैटॉइड अर्थराइटिस। रोग गंभीर है लेकिन जीन थेरेपी और अन्य आधुनिक इलाज से इस मर्ज को काबू में लाया जा सकता है। स्पाइनल र्यूमैटॉइड अर्थराइटिस ऐसी बीमारी है, जिसमें हमारे शरीर का रोग-प्रतिरोधक तंत्र (इम्यून सिस्टम) हमें बचाने के बजाय हमारे शरीर पर ही आक्रमण करने लग जाता है। इस रोग में शरीर का रोग-प्रतिरोधक तंत्र हमारे शरीर के खिलाफ उसमें बनने वाले प्रोटीन, हड्डियों में स्थित कणों, जोड़ों, इंटरवर्टिब्रल डिस्क (आई. वी. डी) और रीढ़ की मांसपेशियों को खत्म करने लग जाता है। इसके परिणामस्वरूप हमारे जोड़ खराब होने लग जाते हैं, जिससे रीढ़ में विकार आ जाता है, जिसे हम स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं।

रोग का दुष्प्रभाव

स्पाइनल र्यूमैटॉइड अर्थराइटिस के कारण आने वाले अधिकतम बदलावों को पलटा नहीं जा सकता। इसके परिणामस्वरूप रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए कार्य करना बंद कर देती है या फिर इसमें अकड़न रह जाती है। ज्यादातर यह माना जाता है कि यह बीमारी लाइलाज है और इसके साथ ताउम्र रहना पड़ेगा। यह रोग कम उम्र खासतौर पर किशोरावस्था में शुरू हो सकता है। रोगी की गंभीरता को देखा जाए, तो इसका प्रभाव न सिर्फ रोगी के शरीर पर परंतु पीड़ित व्यक्ति के मस्तिष्क 58 और सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर भी पड़ता है।

बीमारी के लक्षण

जोड़ों में सूजन, अकड़न या लालिमा होना, थकावट महसूस करना, तेज बुखार होना र्यूमैटॉइड अर्थराइटिस के प्रमुख लक्षण हैं। यह रोग कम आयु में प्रारंभ हो जाता है, जिससे जल्दी ही रीढ़ की हड्डी में विकार और सूजन बढ़ जाती है। अंततः रीढ़ की हड्डी का स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है।

परंपरागत इलाज

परंपरागत इलाज के अंतर्गत र्यूमैटॉइड अर्थराइटिस में शुरुआती तौर पर तेज एंटी-इनफ्लेमेटरी दवाएं दी जाती हैं। दवा का प्रभाव बढ़ाने के लिए एंजाइम्स (ओरल फॉर्म टैब्लेट या कैप्सूल के रूप में) भी दिए जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर पल्स थेरेपी-भी कुछ समय के लिए देते हैं। इसमें स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। इलाज के दौरान डॉक्टर डिजीज मॉडीफाइंग ड्रग्स भी देते हैं। ये उपचार स्थायी रूप से बीमारी को ठीक नहीं करते, बस रोगी के लक्षणों में अल्पकालिक राहत प्रदान करते हैं।

स्टाइलिश दिखने के लिए चुनें सही आईवेयर

स्टाइलिश और अट्रैक्टिव दिखना चाहती हैं तो कलरफुल व डिजाइनर सनग्लासेस ट्राई करें। इन दिनों स्क्वेयर, रेक्टैंगुलर व हाफ फ्रेम वाले, कैट आई शेप वाले गॉगल्स अभी भी ट्रेंड में है...

स्टाइलिश और अट्रैक्टिव

स्टाइलिश और अट्रैक्टिव दिखना चाहती हैं तो कलरफुल व डिज़ाइनर सनग्लासेस ट्राई करें। इन दिनों स्क्वेयर, रेक्टैंगुलर व हाफ फ्रेम वाले सनग्लासेस ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं।

कैट आई शेप

कैट आई शेप वाले गॉगल्स अभी भी टेंड् में हैं लेकिन कलरफुल फ्रेम्स वाले गॉगल्स की बात ही कुछ अलग है।

स्पोर्टी लुक गॉगल्स

स्पोर्टी लुक के लिए स्क्वेयर शेप वाले ये गॉगल्स आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देंगे।

हाफ फ्रेम वाले गॉगल्स

हाफ फ्रेम वाले ये गॉगल्स अट्रैक्टिव लुक के लिए पसंद किए जाते हैं।

मोटे फ्रेम वाले गॉगल?स

रेट्रो स्टाइल के मोटे फ्रेम वाले गॉगल्स यंगस्टर्स की पहली पसंद हैं। ये रेट्रो के साथ कैजुअल लुक भी देते हैं।

एविएटर शेप वाले गॉगल्स

स्टाइलिश दिखने के लिए एविएटर शेप वाले गॉगल्स को ट्राई करें।

रोज खाएं मुट्ठीभर भीगे हुए चने, फिर देखिए कमाल

बादाम यादाशत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। बच्चों ही नहीं बड़ों के लिए भी यह बहुत फायदेमंद होते हैं।

इसमें विटामिन इ, जिंक, कैल्शियम,मैग्नीशियम,मिनरल्स और ओमेगा- 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं लेकिन बादाम की तुलना में चना कम कीमत में ज्यादा फायदे देता है। इसमें आयरन, प्रोटीन और कई मिनरल्स पाए जाते हैं। जो शरीर को एनर्जी देते हैं।

1. कमजोरी करे दूर

इनमें आयरन, प्रोटीन और मिनरल्स काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसे खाने से शरीर को कई एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। इसके सेवन से कमजोरी दूर होती है।

2. हार्ट डीजीज

चना खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। इससे हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है और हार्ट हेल्दी रहता है।

3. एनीमिया में फायदेमंद

इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। अगर आप एनीमिया की समस्या से परेशान हैं तो रोजाना चना खाने से इस समस्या से छुटकारा मिलेगा।

4. किडनी की सफाई

चने में फॉस्फोरस होता है जो हीमोग्लोबिन का लेवल बढाता है और किडनी से एक्स्ट्रा साल्ट निकालता हैं।

5. हेल्दी स्किन

इसे चबा कर खाने से स्किन हेल्दी और ग्लोइंग रहती है।

इसका रोजाना सेवन करने से स्किन से जुड़ी कई समस्याओं जैसे- खुजली और रैशेज से छुटकारा मिलता है।

6. यूरिन प्रॉब्लम

अगर आप बार-बार यूरिन जाने की समस्या से परेशान हैं तो भीगे चनों को गुड़ के साथ खाएं। ऐसा करने से इस प्रॉब्लम से राहत मिलेगी।

हेयर रिंग से दें बालों को नया स्टाइल

परफेक्ट मेकअप, हेयर स्टाइल और ड्रेस आपको स्टाइलिश दिखाता है। अगर आपका हेयर स्टाइल अच्छा न हो तो आपकी लुक खराब हो जाती हैं। बालों में स्टाइलिश लुक देने के लिए आजकल कई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि हेयर रिंग। हेयर रिंग का इस्तेमाल करके आप सबसे अलग दिख सकती है। आजकल लड़कियां खूब हेयर रिंग बालों का यूज कर रही हैं। आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप हेयर रिंग का इस्तेमाल बालों को स्टाइलिश दिखा सकती हैं।

- हेयर रिंग बनाने के लिए आपको चोटी बनाना बहुत जरूरी है इसलिए सबसे पहले बालों की चोटी बना लें।
- हेयररिंग ज्यादा फ्रेंच, बॉक्सर और डबल डच हेयर स्टाइल पर अच्छे लगते हैं।
- अब इन्हें चोटी पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर लगाएं।
- ये रिंग्स बालों पर आसानी से ऐडजस्ट हो जाती हैं। इनको आप कोई डिजाइन देकर भी लगा सकती है।
- आप चाहें तो इन्हें अलग-अलग डिजाइन देकर लगा सकती है जिससे आपके बाल सुंदर लगें।

ऐसे दूर करे आंखों की थकान

खूबसूरत आंखे हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यह जरूरी नहीं कि आंखे सिर्फ मेकअप के साथ ही खूबसूरत दिखती है। नींद न पूरी होना या काम का प्रशेर अधिक होने से हमारी आंखे थकी-थकी लगती है, जिससे चेहरे की खूबसूरती कम हो जाती है।

आईब्रो पेंसिल: आंखों की थकान छुपाने के लिए आईब्रो पेंसिल का इस्तेमाल करें। अपनी आईब्रो को पेंसिल के साथ भरें। इससे आंखों की थकान भी छिप जाएगी और उन्हें नया लुक भी मिलेगा।

ठंडे खीरे के स्लाइस: अपनी आंखों को खीरे के स्लाइस से ढके। इससे आंखों की थकान दूर होगी।

आईशैडो: आईशैडो के साथ अपनी आंखों की थकान को छुपाएं। इसके लिए कुछ खास तरह से आईशैडो लगाएं। ऐसा करने से आपकी आंखे सुंदर भी दिखेगी।

क्लीनजिंग और मॉइस्चराइजर: स्किन की क्लीनजिंग करके आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारें। इसके बाद मॉइस्चराइजिंग क्रीम से हल्के हाथों से आंख के आस-पास मसाज करें। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आंखों की थकान दूर होगी।

रेसिपी

मसाला मशरूम

सामग्री

1 कटा टमाटर, 1 कटी प्याज,1 टुकड़ा दालचीनी, 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 6-7 लौंग,6-7 छोटी इलायची, 2 छोटे चम्मच तेल,1 छोटा चम्मच पिसी लाल मिर्च, नमक स्वादानुसार, 250 ग्राम कटा मशरूम, 1 कटोरी हरा धनिया।

विधि

इस को बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सर में टमाटर, प्याज, दालचीनी और अदरक-लहसुन का पेस्ट, लौंग, इलायची और थोड़ा पानी डालकर पीस लें। अब एक पैन में तेल गर्म होने के बाद इस पेस्ट को डालकर कुछ देर भूनें फिर उसमें पिसी लाल मिर्च और नमक मिलाएं। सब चीजों को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद उसमें मशरूम डालें। फिर से सब सामग्रियों के साथ मशरूम को मिलायें और अब 5—7 मिनट तक ढक कर पकाएं। अब उसको सर्विंग बाउल में ढालकर धनिया पत्ता से गार्निश करें और गरमागरम सर्व करें।

चॉकलेट लावा केक

सामग्री

200 ग्राम चॉकलेट
110 ग्राम मक्खन
3 अंड़े
60 ग्राम चीनी
1 टीस्पून वैनिला एक्सट्रेक्ट
30 ग्राम मैदा

विधि

एक पैन लेकर उसमें पानी डाल दें और इसमें चॉकलेट डालकर गर्म करें। इसमें मक्खन डालकर अच्छे से मिलाएं ताकि यह पिघल जाए। एक अलग बाऊल लेकर उसमें 2 अंड़े और1अंड़े का पीला भाग मिलाकर फैट लें। इसमें अब वनीला एसैंस और चीनी डालकर मिक्स कर लें। इसमें मैदा डालकर मिला लें। इसके बाद इसमें पिघली हुई चॉकलेट और मक्खन का मिक्सचर डालकर मिला लें। ध्यान रखें इसमें गांठ न पड़े। अब कप केक के पेपर सांचों पर मक्खन लगाएं ताकि केक इस पर चिपके न और इस पर थोड़ा मैदा छिड़क दें। इसमें अब केक का मिक्सचर डाल दें। ओवन को 350एस्न/180एष्ट पर प्री हीट करें और इसमें 5-10 मिनट के लिए कप केक को रखें। बेकिंग के बाद केक को सांचे से निकाल कर प्लेट में रखें और इसे चॉकलेट सिरप से गार्निश करें। वनिला आइसक्रीम के साथ इसे सर्व करें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

नितिन नवीन के स्वागत पर वीएचपी की आपत्ति

नईदिल्ली। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत कार्यक्रम के दौरान भगवान हनुमान की प्रतिकृति के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इस मामले पर विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया है. वीएचपी ने मामले में जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने और उचित कार्रवाई की मांग की है. संगठन का कहना है कि धार्मिक प्रतीकों का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.दरअसल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पिछले दिनों लखनऊ पहुंचे थे. इस दौरान, उनकी स्वागत यात्रा में भगवान हनुमान की प्रतिकृति के इस्तेमाल का मामला सामने आया. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया. वीएचपी के केंद्रीय मंत्री अम्बरीश ने मामले की निंदा की है. उन्होंने कहा कि भगवान की प्रतिकृति का इस तरह सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में उपयोग अनुचित है।

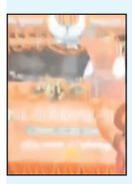

क्या हम सीएम को रेगुलेट करें: सुप्रीम कोर्ट

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डीएमके की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और टीवीके के अन्य नेताओं को सितंबर 2025 में करूर में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलने या सार्वजनिक बयान देने से रोकने की मांग की गई थी.जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक मंच नहीं बनाया जाना चाहिए. बेंच ने याचिका के आधार पर ही सवाल उठाते हुए कोर्ट ने खुद इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. बेंच ने सवाल उठाते हुए कहा, जिस सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं, वह किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की याचिका को कैसे स्वीकार कर सकता है? अपनी याचिका में, पूर्व सत्ताधारी डीएमके ने टीवीके मंत्री आधव अर्जुन की कथित टिप्पणियों पर कार्रवाई की मांग की. उनका कहना था कि इन बयानों से गवाह प्रभावित हो सकते हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी को कोर्ट से राहत

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स हैंडल तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है. केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि नीट री-टेस्ट से पहले मची खलबली को रोकने के लिए इस अकाउंट पर रोक लगाई गई थी. सरकार ने कहा कि परीक्षा अब पूरी हो चुकी है, इसलिए अकाउंट से रोक हटाने में अब कोई आपत्ति नहीं है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की याचिका पर सुनवाई कर रही थीं. दिपके ने 21 मई को अपने एक्स हैंडल को ब्लॉक किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत बताते हुए चुनौती दी थी. कोर्ट के आदेश के कुछ ही देर बाद पार्टी का मूल हैंडल दोबारा शुरू हो गया है. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि 21 जून को होने वाली नीट री-टेस्ट परीक्षा से पहले छात्रों और अभिभावकों के बीच किसी भी तरह की अराजकता या भ्रम को टालने के लिए इस सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक किया गया था।

बांकीपुर उपचुनाव के लिए भाजपा ने उतारा उम्मीदवार

नईदिल्ली। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. बांकीपुर सीट से अभिषेक कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है. अभिषेक कुमार भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं. वह पटना महानगर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं. साथ ही दो बार दो बार मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं. मंडल मंत्री एवं महामंत्री के दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं. वह 27 वर्षों से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं.

उन्होंने बूथ अध्यक्ष से राजनीति जीवन की शुरुआत की थी. बीजेपी प्रदेश कार्यालय और बांकीपुर विधानसभा सीट के एक सामान्य कार्यकर्ता को नितिन नवीन ने अपने इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट के लिए उम्मीदवार पसंद किया था. अभिषेक कुमार कायस्थ जाति से आते हैं. वह फिलहाल प्रदेश युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हैं.इससे पहले जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर इस सीट से उम्मीदवार घोषित हुए थे।

24 जुलाई से पहले टीएमसी विवाद सुलझाएगा चुनाव आयोग?

नईदिल्ली। निर्वाचन आयोग तृणमूल कांग्रेस के नाम-निशान और प्रधान विवाद में जल्दी ही अंतरिम फैसला देगा. क्योंकि 24 जुलाई को पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव होने हैं. दोनों गुट अपने अपने प्रत्याशी उतारने के लिए टिकट भी बांटेंगे. हालांकि सोमवार तक दोनों पक्षों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर ही अपने अपने दावे सबूतों के साथ आयोग को सौंप दिए थे. वहीं, सोमवार को ही निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में हाल ही में खाली हुई राज्यसभा की तीन सीटों पर उपचुनाव भी घोषित कर दिया. उधर तृणमूल कांग्रेस के एक गुट की नेता ममता बनर्जी हैं तो दूसरे का नेतृत्व ऋब्रत बनर्जी कर रहे हैं. दोनों का दावा है कि असल तृणमूल कांग्रेस सिर्फ उनके पास है. आयोग के घोषित कार्यक्रम के मुताबिक तीनों सीटों के लिए नामांकन 14 जुलाई तक दाखिल करने होंगे. अगर दोनों गुट अलग-अलग उम्मीदवार नॉमिनेट करते हैं, तो निर्वाचन आयोग को उस तारीख तक ये तय करना होगा।

मोदी की प्रम्बानन मंदिर भ्रमण के साथ इंडोनेशिया दौरा पूरा

इंडोनेशिया में महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय की गूंज

नईदिल्ली। प्रम्बानन मंदिर परिसर पहुंचने पर मोदी का पारंपरिक स्वागत किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के साथ प्राचीन स्थल का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी साफ दिखी, जब उन्होंने हाथ मिलाए और मंदिर परिसर के केंद्रीय शिखरों की पृष्ठभूमि में फोटो खिंचवाई। अपनी यात्रा के दौरान मोदी को इंडोनेशिया-इंडिया कोलैबोरेटिव कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन फॉर प्रम्बानन टेंपल कंपाउंड नामक एक औपचारिक पैनल पर परियोजना और मंदिर के इतिहास की झलक भी दी गई। इसमें परियोजना के डिजाइन और अपेक्षित परिणाम का विवरण भी था। मोदी का इंडोनेशियाई लोगों के एक समूह ने पारंपरिक मंत्रों और घंटियों की मधुर ध्वनि से स्वागत किया।

प्रधानमंत्री मोदी के प्रम्बानन मंदिर दौरे के बाद दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति सुबियांतो ने 2029 से पहले जीर्णोद्धार पूरा करने का वादा लिया है। वे योजना बनाकर काम करते हैं, ऐसे में पूरा भरोसा है कि काम पूरा होगा और वे इंडोनेशिया आकर एकसाथ इसका जश्न मनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इस गौरवशाली स्थल के जीर्णोद्धार का हिस्सा बनने को लेकर उन्हें गर्व है। उन्होंने कहा, एक हजार साल से भी अधिक पुराना प्रम्बानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया

की साझा सांस्कृतिक विरासत का एक शाश्वत प्रतीक है। संयुक्त संरक्षण परियोजना में भारतीय पक्ष से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) प्रमुख एजेंसी होगी।

योग्याकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो के साथ प्रम्बानन मंदिर परिसर का भ्रमण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति सुबियांतो ने 2029 से पहले इस जीर्णोद्धार को पूरा करने के बाद एक बार फिर से इंडोनेशिया दौरा करने की बात कही है। उन्हें पूरा भरोसा है कि काम पूरा होगा। सरकार के मुताबिक पीएम मोदी के दौरे का उद्देश्य 2018 की भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत व्यापार, सुरक्षा और दुर्लभ-पृथ्वी खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों को जोड़ती है। इंडोनेशिया के लोग प्रम्बानन मंदिर परिसर की महान विरासत को संरक्षित करने के लिए धन्यवाद के पात्र हैं।संयुक्त संरक्षण परियोजना के उद्घाटन का हिस्सा बनना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा, मैंने जो बातचीत सुनी है, उससे पता चलता है कि यहां की हवाओं में संस्कृति की सुगंध है। वह सुगंध जिसे हम भारत की धरती पर हर पल महसूस करते हैं। यह सुगंध, यह सांस्कृतिक विरासत, हमें जोड़ती है।

बकौल पीएम मोदी, 1200 साल से इंडोनेशिया के लोगों ने इस महान विरासत को संरक्षित रखा है। इसे पूरी श्रद्धा और श्रद्धा के साथ किया है। इसलिए, मैं इंडोनेशिया के लोगों और अब तक के सभी शासकों को भी तहे दिल से सलाम करता हूं। मैंने इस मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय के जाप होते देखे; इसने वास्तव में मेरे दिल को छू लिया। उन्होंने कहा, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर में संरक्षण और जीर्णोद्धार का काम शुरू होने के साथ ही, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय पर्यटक निश्चित रूप से इस स्थान का दौरा करेंगे।

ममता बनर्जी की रैली में भिड़े टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ता

बालीगंज। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी नेत्री ममता बनर्जी की रैली के दौरान जमकर हंगामा और बवाल हुआ। बालीगंज फाड़ी से हाजरा मोड़ के बीच निकाले जा रहे इस मार्च में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मीडिया के ताजा फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे दोनों तरफ के लोग एक-दूसरे से बुरी तरह उलझ पड़े। इस हंगामे के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव फैल गया है।

यह हाई-वोल्टेज ड्रामा उस समय शुरू हुआ जब टीएमसी नेता ममता बनर्जी की अगुवाई में पार्टी का जुलूस बालीगंज फाड़ी से हाजरा मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान वहां भाजपा के समर्थक भी पहुंच गए और दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। पहले दोनों तरफ से तीखी बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते धक्का-मुक्की में बदल गई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को धक्का देते हुए चोर, चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई।

इस रैली को लेकर कल ही कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने समय सीमा और रूट में कुछ बदलाव करते हुए इसे आयोजित करने की अनुमति दी थी। अदालत के आदेश के बाद सुरक्षा के दावे तो किए गए थे, लेकिन जैसे ही मार्च हाजरा मोड़ की तरफ बढ़ा, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता सड़क पर आ गई। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति को संभाला, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है।

यह पूरा बवाल बारुईपुर में 11 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में ही शुरू हुआ था। इस खौफनाक वारदात के खिलाफ टीएमसी के छात्र-युवा संगठन ने न्याय की मांग को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद कोलकाता में यह रैली निकाली थी। चूंकि इस घटना के मुख्य आरोपी प्रभा मंडल का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है, इसलिए राज्य में पहले से ही सियासी पारा चढ़ा हुआ था। बस इसी गुस्से और राजनीति के चलते जब यह मार्च बालीगंज फाड़ी से हाजरा मोड़ की तरफ बढ़ रहा था, तो टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और शांतिपूर्ण रैली देखते ही देखते अखाड़ा बन गई।

बंगाल पुलिस के बाद ईडी की कार्रवाई

टीएमसी के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से जुड़े संदिग्ध फंड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के तहत अपनी जांच तेज कर दी है। केंद्रीय एजेंसी ने कोलकाता में टीएमसी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें लगभग 440 करोड़ रुपये जमा हैं।

यह पूरी कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा तीन मुख्य बैंक खातों पर लगाए गए डेबिट फ्रीज के बाद हुई है। पुलिस ने बागी विधायकों के एक गुट की शिकायत के बाद इन खातों से होने वाले सभी लेन-देन और निकासी पर रोक लगा दी थी। इस गुट का नेतृत्व ऋब्रत बनर्जी कर रहे हैं। अब ईडी ने इस मामले को अपने हाथ में लेकर जांच का दायरा बढ़ा दिया है।

जांच के तीन मुख्य बिंदु

हवाई कंपनियों पर शक : ईडी की शुरुआती जांच के मुताबिक, 150 करोड़ रुपये से ज्यादा का संदिग्ध फंड एविएशन और ट्रैवल कंपनियों के जरिए भेजा गया था।

कोलकाता में ताबड़तोड़ छापेमारी: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के साथ ईडी की टीमों ने कोलकाता में कई ठिकानों पर छापे मारे। यह छापेमारी एक प्राइवेट चार्टर फर्म केयरवेल एविएशन, उसके निदेशकों और एक कथित इलेक्टोरल ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई।

संदेह का घेरा : जांच एजेंसी इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि क्या इन खातों का इस्तेमाल भ्रष्टाचार, जबरन वसूली या स्थानीय तस्करी से कमाए गए पैसों को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था।

इस वित्तीय प्रतिबंध के खिलाफ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी के मुख्य गुट ने कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। पार्टी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस रोक को चुनौती दी है। टीएमसी का तर्क है कि फंड ब्लॉक होने से उनकी राजनीतिक गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई हैं। अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है। दूसरी तरफ, यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब हालिया चुनावी झटकों के बाद पार्टी की संपत्तियों और फंड पर नियंत्रण को लेकर टीएमसी के भीतर ही एक गंभीर अंदरूनी पावर स्ट्रगल चल रहा है।

इस पूरे विवाद की जड़ें हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव और उसमें तृणमूल कांग्रेस को लगे बड़े झटकों से जुड़ी हैं। चुनावी हार के तुरंत बाद पार्टी के भीतर फंड और संपत्तियों पर नियंत्रण को लेकर एक अंदरूनी जंग छिड़ गई, जिसने तब बड़ा रूप ले लिया जब विधायक ऋब्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागी विधायकों के एक गुट ने स्थानीय पुलिस में पार्टी के ही वित्तीय प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गंभीर शिकायतें दर्ज करा दीं। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले टीएमसी के तीन मुख्य बैंक खातों पर डेबिट फ्रीज लगाकर लेन-देन रोका, जिसके बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एंट्री मारते हुए जांच को मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के तहत अपने हाथ में ले लिया और कोलकाता में मौजूद करीब 440 करोड़ रुपए के चुनावी खजाने को पूरी तरह सीज कर दिया।

खेल
प्रमुख समाचार

चौथे टी20 मैच में श्रृंखला बचाने उतरेगी भारतीय टीम

ब्रिस्टल। लगातार दो मैच हारने के बाद श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली भारतीय टीम जब बृहस्पतिवार को यहां श्रृंखला के निर्णायक चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड के सामने होगी तो उसके सामने खिलाड़ियों के चयन को लेकर मुश्किल चुनौतियां होगी। भारतीय टीम इंग्लैंड के मुश्किल हालात में ढलने के लिए संघर्ष कर रही है और टीम यह मैच हार गई तो सीरीज भी गंवा देगी। टीम चयन को लेकर सबसे बड़ा सवाल संजू सैमसन को लेकर है। उन्हें दूसरे और तीसरे टी20 से बाहर कर 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया था।

इस युवा खिलाड़ी का प्रदर्शन अब तक टीम के बाकी खिलाड़ियों से न तो खराब रहा है और न ही बहुत अच्छा। चूंकि टीम अभी 0-2 से पीछे चल रही है इसलिए भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने सैमसन की वापसी की संभावना से इनकार नहीं किया है। संजू का करियर पिछले चार महीनों में काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। एक समय वह टीम से बाहर थे, फिर शानदार प्रदर्शन कर टीम में लौटे, लेकिन अब फिर उन्हें बाहर बैठना पड़ा है।

तीसरे टी20 में 125 रन की करारी हार के बाद ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम के बाहर प्रशंसकों ने वी वांट संजू (हमें संजू टीम में चाहिए) के नारे लगाए। टी20 विश्व कप दिलाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव को बाहर करने पर भारी आलोचना हुई थी। अब उसी टूर्नामेंट के नायक सैमसन को नजरअंदाज करने के फैसले ने एक और सार्वजनिक विरोध को हवा दे दी है। ट्रेंट ब्रिज में शर्मनाक हार ने टीम की कमियों और टीम प्रबंधन की स्पष्ट योजना की कमी को भी उजागर कर दिया है।

भारत के लिए सीरीज बचाने की चुनौती है, ऐसे में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज बृहस्पतिवार को चुनौती और बढ़ाना चाहेंगे और शनिवार को साउथम्प्टन में होने वाले आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय से पहले ही सीरीज अपने नाम करना चाहेंगे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 1,677 अंक लुढ़का निफ्टी 23,882 पर बंद

नईदिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर बुधवार को भारतीय शेयर बाजार पर भी साफ देखने को मिला। निवेशकों में बढ़ी चिंता और बिकवाली के दबाव के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 1,677.12 अंक यानी 2.15 प्रतिशत गिरकर 76,503.60 पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई निफ्टी 50, 516.65 अंक यानी 2.12 प्रतिशत टूटकर 23,882.05 के स्तर पर आ गया। निफ्टी 50 इंडेक्स में सबसे अधिक नुकसान जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरग्लोब एविएशन और श्रीराम फाइनेंस के शेयरों में देखने को मिला। पूरे कारोबारी सत्र के दौरान बिकवाली का दबाव इतना ज्यादा रहा कि निफ्टी 50 के केवल चार शेयर ही बढ़त के साथ बंद हो सके, जबकि बाकी सभी शेयर लाल निशान में रहे।

पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव कच्चे तेल में आई बड़ी तेजी

नईदिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर एक बार फिर कच्चे तेल के बाजार पर दिखने लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच हालात बिगड़ने से वैश्विक तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी बीच अमेरिका में भी कच्चे तेल और पेट्रोल-डीजल का भंडार लगातार घट रहा है। इन दोनों वजहों से बुधवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 72 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई। इस हफ्ते अब तक तेल में 5 फीसदी से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ा तनाव है। अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए हैं और ईरानी कच्चे तेल की बिक्री से जुड़ी एक अहम छूट भी वापस ले ली है। रिपोर्ट के मुताबिक, कतर के एक एलएनजी जहाज और सऊदी अरब के एक तेल टैंकर को भी निशाना बनाया गया।

यूबीएल ने 2024-25 में 43000 करोड़ रुपए का योगदान दिया

नई दिल्ली। अग्रणी शराब विनिर्माता हेनकेन कंपनी की इकाई यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड (यूबीएल) ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था में 43,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया। एक अध्ययन रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। एम्सटर्डम स्थित सलाहकार फर्म स्टूवर्ड रेडक्रीन की सामाजिक अध्ययन रिपोर्ट कहती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में यूबीएल के इस योगदान में मूल्य श्रृंखला के दौरान चुकाए 30,600 करोड़ रुपए के कर भी शामिल हैं। यह राशि राज्यों के कुल कर राजस्व का 1.3 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 0.1 प्रतिशत के बराबर है। रिपोर्ट के मुताबिक, उपभोक्ताओं द्वारा बीयर पर खर्च किए गए हर 100 रुपये में से करीब 63 रुपए राज्य सरकारों के पास जाते हैं, जो सार्वजनिक सेवाओं एवं बुनियादी ढांचे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।

अब रुपये में होगी एफपीआई फीस की पेमेंट

नईदिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) नियमों में बदलाव करते हुए शुल्क भुगतान की व्यवस्था को अमेरिकी डॉलर की जगह भारतीय रुपये में कर दिया है। यह बदलाव विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों (FVCI) दोनों पर लागू होगा। नए नियम छह महीने बाद प्रभावी होंगे, ताकि विदेशी निवेशकों को नई व्यवस्था अपनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। 3 जुलाई की अधिसूचना के अनुसार, एफपीआई नियमों के रेगुलेशन 43बी (2) में 1,000 अमेरिकी डॉलर की जगह अब 90,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। सेबी ने कैटेगरी-I एफपीआई और FVCI के रजिस्ट्रेशन शुल्क को 2,500 डॉलर से बदलकर 2.3 लाख रुपये कर दिया है।

चुनौतियों से घिरा है सहकारिता आंदोलन, इस क्षेत्र में गुजरात और महाराष्ट्र सबसे आगे

अरविंद कुमार

राष्ट्रीय राजधानी में भारत मंडपम में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के पांच साल पूरे होने के मौके पर आयोजित विशेष समारोह में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक नई सहकारी जीवन बीमा कंपनी के गठन की घोषणा के साथ कई उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि पहले यह एक उपेक्षित आंदोलन था जो अब शक्तिमान है। पहले मुख्यतया सहकारी समितियां प्राथमिक स्तर तक ही सीमित थीं, पर उनका विविधीकरण कर उसे कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण तथा ग्रामीण सेवाओं के दायरे में लाने का काम किया गया है। सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी की प्रगति बहुत संतोषजनक है और आगे इसका विस्तार 500 शहरों में होगा।

बेशक नया मंत्रालय बनने के बाद कई क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन का विस्तार हो रहा है, पर अभी इस क्षेत्र में कई गंभीर चुनौतियां कायम हैं। सहकारिता के लिहाज से देश के विकसित राज्यों में गुजरात और महाराष्ट्र ही सबसे प्रमुख हैं। अन्य अग्रणी राज्यों में हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब और तमिलनाडु भी हैं। पर उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में इस आंदोलन की दशा अभी भी ठीक नहीं है और इसके लिए ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है।

पर देश में सहकारिता आंदोलन को एक बड़ी शक्ति बनाने की संभावनाएं बरकरार हैं। सहकारी समितियों और उनके सदस्यों की संख्या के मामले भारत विश्व में अग्रणी है। देश भर में 8.5 लाख सहकारिता संगठनों से 30 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हैं। कृषि ऋण वितरण में लगभग 29% हिस्सा सहकारिता क्षेत्र का है। अन्य क्षेत्रों में उर्वरक वितरण में 35%, उर्वरक उत्पादन में 25%, चीनी उत्पादन में 35%, गेहूं खरीद में 13%,

धान खरीद में 20% हिस्सा सहकारिता क्षेत्र का है।

इसमें संदेह नहीं कि 2021 में कृषि मंत्रालय से अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन होने के बाद इस क्षेत्र में नई गतिशीलता आई है। तभी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया था। अलग बजट होने से पहले की तुलना में काफी अधिक संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं और नए प्रयोग भी हो रहे हैं। 2026-27 में सहकारिता क्षेत्र का बजट 1744.74 करोड़ आवंटित करने के साथ बजट में सहकारी क्षेत्र को कई रियायतें दी गई हैं। राज्यों की आशंकाओं को दूर करते हुए 24 जुलाई, 2025 को नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति भी बनी। फिर व्यापक विचार मंथन के बाद पर्यटन, टैक्सी, बीमा और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से सहकारी क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए व्यापक योजना तैयार की गई, जो जमीन पर उतरने लगी है।

सहकारी समितियों के नियमित चुनाव के लिए सहकारी चुनाव प्राधिकरण का गठन 11 मार्च, 2024 को किया जा चुका है। मार्च 2024 में तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियों- भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के कामकाज में तब और तेजी आई जब दिल्ली में उनके नए कार्यालय भवन बने। यही नहीं, 125 एकड़ क्षेत्र में 500 करोड़ रु. की लागत से आणंद में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय भी आकार ले रहा है, जिसमें सहकारिता में नीति निर्माण, डाटा विश्लेषण व देश के कोऑपरेटिव के विकास के लिए समयबद्ध योजना और रणनीति बनाने का काम होगा।

नए कृषक उत्पादक संगठन या एफपीओ की स्थापना सहकारिता क्षेत्र में एक नई पहल है। डेयरी, पेट्रोल पंप, गैस की एजेंसी, सस्ती दवाई की दुकान, सस्ते गल्ले की दुकान, भंडारण, हर घर जल समेत 22 तरह के कामों से पैक्स को जोड़ने की पहल की गई है ताकि उनकी माली हालत बेहतर हो और वे बहुउद्देशीय भूमिका में हों। एफपीओ योजना में पैक्स के एकीकरण से किसान अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का दायरा विस्तृत कर सकेंगे और इससे छोटे और सीमांतों को फायदा होगा। इन कामों के विस्तार के साथ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की भूमिका भी लगातर बढ़ रही है।

एस.डी.जी. 2.0 और बस्तर अंजोर पहल का शुभारंभ

राज्य स्तर पर 343 और जिला स्तर पर 99 संकेतकों के माध्यम से होगी विकास कार्यों की प्रभावी निगरानी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की उपस्थिति में राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. 2.0 फ्रेमवर्क का विमोचन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. राज्य एवं जिला संकेतक फ्रेमवर्क 2.0 तथा मेटाडेटा हैंडबुक का भी विमोचन किया गया। साथ ही बस्तर संभाग के समावेशी, अभिसरण आधारित और मापनीय विकास के लिए तैयार की गई अभिनव पहल बस्तर अंजोर की भी शुरुआत की गई।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, सटीक डेटा और परिणाम आधारित मॉनिटरिंग अत्यंत आवश्यक है। एस.डी.जी. 2.0 फ्रेमवर्क शासन को साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, बेहतर अंतर-विभागीय समन्वय तथा योजनाओं की नियमित निगरानी के लिए एक सशक्त आधार प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल %विकसित छत्तीसगढ़ @2047% के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल विकास योजनाएं संचालित करना नहीं, बल्कि उनके वास्तविक प्रभाव को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। एस.डी.जी. 2.0 के माध्यम से विकास की प्रगति को अधिक पारदर्शी, मापनीय और जवाबदेह बनाया जा सकेगा। सरकार नए एस.डी.जी. 2.0 फ्रेमवर्क के अंतर्गत राज्य स्तर पर संकेतकों की संख्या 275 से बढ़ाकर 343 तथा जिला स्तर पर 82 से बढ़ाकर 99 कर दी गई है। इससे विकास कार्यों की अधिक व्यापक, सटीक और वैज्ञानिक निगरानी संभव होगी। मेटाडेटा हैंडबुक में प्रत्येक संकेतक की गणना पद्धति एवं रिपोर्टिंग प्रणाली को मानकीकृत किया गया है, जिससे पूरे राज्य में डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी।

इस अवसर पर राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने बस्तर अंजोर की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए बताया कि यह अभिसरण (कन्वर्जेंस) आधारित विकास मॉडल है, जिसे बस्तर संभाग को देश का सर्वाधिक विकसित जनजातीय क्षेत्र बनाने के संकल्प को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

उन्होंने बताया कि %बस्तर अंजोर% के 3+4 मॉडल के अंतर्गत जिला स्तर की तीन प्रमुख पहल - नियद नेल्लानार 2.0, बस्तर मुन्ने और स्वस्थ बस्तर - का अभिसरण चार प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विकास फ्रेमवर्क - एस.डी.जी. 2030, विकसित छत्तीसगढ़ ञ2047, आकांक्षी जिला एवं विकासखंड कार्यक्रम से किया गया है। इसका उद्देश्य अतिरिक्त संसाधनों के बिना बेहतर समन्वय के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और अधोसंरचना जैसे क्षेत्रों में ठोस एवं मापनीय परिणाम प्राप्त करना है।

%बस्तर अंजोर% अंत्योदय से सर्वोदय की भावना पर आधारित एक दूरदर्शी पहल है, जो बस्तर को समावेशी, सतत एवं परिणामोन्मुख विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, मंत्रिपरिषद के सदस्य, मुख्य सचिव श्री विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना की शुरुआत

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन के सभागार में राज्य के शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने योजना के ब्रोशर का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने इसे कर्मचारी कल्याण, सुशासन और संवेदनशील प्रशासन की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य शासकीय सेवकों को आकस्मिक परिस्थितियों में सम्मानजनक, त्वरित और सहज वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शासकीय सेवक राज्य के विकास की रीढ़ हैं। जब कर्मचारी आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर कार्य करेंगे, तभी शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा।उन्होंने कहा कि अब कर्मचारियों को आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए निजी साहूकारों अथवा ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेने की विवशता का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था विकसित की है, जिसके माध्यम से वे बिना अनावश्यक कागजी प्रक्रिया के अपनी पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करते हुए इस सुविधा को ई-कोष प्रणाली से एकीकृत किया है। यह व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल, पेपरलेस, सुरक्षित और पारदर्शी है तथा इससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं आएगा। उन्होंने इस अभिनव पहल के लिए वित्त विभाग की टीम को बधाई देते हुए सभी शासकीय सेवकों से विकसित छत्तीसगढ़ और सुशासन के संकल्प को आगे बढ़ाने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। भविष्य में बेहतर क्रेडिट स्कोर वाले कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर अधिक राशि के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने की भी योजना है।

लोकसंस्कृति की अप्रतिम धरोहर तीजन बाई को दी गई श्रद्धांजलि

रायपुर। संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आज रायपुर स्थित मुक्ताकाशी मंच, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में पद्म विभूषण, अंतरराष्ट्रीय पंडवानी गायिका डॉ. तीजन बाई को समर्पित सांगीतिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेशभर के कलाकारों, साहित्यकारों, संस्कृति प्रेमियों एवं गणमान्य नागरिकों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित किए।

इस मौके पर संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल द्वारा डॉ. तीजन बाई की स्मृति को चिरस्थायी बनाने हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं, पद्म विभूषण डॉ. तीजन बाई जी के नाम पर पंडवानी कला के क्षेत्र में प्रतिवर्ष राज्य सम्मान प्रदान किया जाएगा।

गनियारी ग्राम को 'कलाग्राम' के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे लोककलाओं एवं सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण को नई दिशा मिलेगी।डॉ. तीजन बाई जी के प्रिय तंबूरे को रायपुर स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में संरक्षित एवं प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि उनकी स्मृतियाँ और लोकसाधना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहें।

डॉ. तीजन बाई केवल एक महान लोकगायिका नहीं थीं, बल्कि वे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक अस्मिता, लोकपरंपरा और गौरवशाली विरासत की सशक्त पहचान थीं। उनकी अमर लोकधुनें और पंडवानी की विलक्षण शैली सदैव जनमानस को अपनी संस्कृति और लोकमूल्यों से जोड़ती रहेंगी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्रा, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास आयोग की अध्यक्षा सुश्री मोना सेन तथा संस्कृति विभाग के संचालक डॉ. संजय कन्नौजे सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों एवं गणमान्य जनों की गरिमामय उपस्थिति रही।

भूपेश बघेल पंजाब कांग्रेस में भी सुलगाई बगावत : पाण्डेय

रायपुर। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब कांग्रेस में मची भीषण अंतर्कलह और प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल की भारी राजनीतिक विफलता पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता व सांसद संतोष पाण्डेय ने तीखा तंज कसा है। पाण्डेय ने कहा कि जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ में अपनी पूरी सरकार और संगठन को डुबा चुका हो, उसे कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब की कलह शांत करने का जिम्मा सौंपा है, जो बेहद हास्यास्पद है। परिणाम सबके सामने है- भूपेश बघेल के पैर पंजाब में पड़ते ही वहाँ कांग्रेस बगावत की आग में पूरी तरह झुलस गई है।

भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता पाण्डेय ने कहा कि पंजाब पहुँचते ही प्रभारी बघेल की जो फजीहत हुई है, वह कांग्रेस के भीतर उनके घटते कद और सांगठनिक नाकामी को दर्शाती है। छत्तीसगढ़ भवन जाने के बजाय सीधे नेता प्रतिपक्ष प्रतापसिंह बाजवा के घर शरण लेने वाले बघेल को खुद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ठेंगा दिखा दिया है। चन्नी ने न तो बघेल से मुलाकात की और न ही कोई सम्पर्क साधा, बल्कि सोशल मीडिया पर एकता में बल है लिखकर सीधे तौर पर बघेल की मौजूदगी और उनके नेतृत्व को बड़ी चुनौती दे डाली है। श्री पाण्डेय ने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि भूपेश बघेल कांग्रेस के लिए कुप्रबंधन के ब्राण्ड एम्बेस्डर बन चुके हैं। वे जहाँ भी जाते हैं, वहाँ फूट, असंतोष और बगावत की नई कहानी शुरू हो जाती है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने ढाई-ढाई साल के खेल में जो रायता फैलाया था।

दिसंबर 2026 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा

■ 15 निकायों एवं दो नवगठित नगर पंचायतों पर होगा निर्वाचन

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, नवा रायपुर में आज राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में आगामी दिसंबर 2026 में प्रस्तावित नगरीय निकायों के आम एवं उप निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश की 15 नगरीय निकायों(जिनमें 4 नगरपालिक निगम, 5 नगरपालिका परिषद तथा 6 नगर पंचायत शामिल हैं, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2026 में समाप्त हो रहा है) के साथ ही दो नवगठित नगर पंचायतों के आम निर्वाचन की तैयारियों एवं शासन स्तर पर की जा रही आवश्यक कार्यवाहियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिन नगरीय निकायों में निर्वाचन प्रस्तावित हैं, उनमें नगरपालिक निगम बीरगांव, भिलाई, भिलाई-चरौदा एवं रिसाली, नगरपालिका परिषद जामुल, सारंगढ़, बैकुण्ठपुर, शिवपुर-चरचा एवं खैरागढ़ तथा नगर पंचायत प्रेमनगर, मारो, कोंटा, नरहरपुर, भैरमगढ़ एवं भोपालपट्टनम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नवगठित नगर पंचायत तमनार एवं बड़ी करेली में भी आम निर्वाचन कराया जाएगा।

बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती आर संगीता ने नगरीय निकायों के परिसीमन एवं आरक्षण की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 15 नगरीय निकायों में महापौर एवं अध्यक्ष पदों का आरक्षण पूर्ण किया जा चुका है तथा वार्ड पार्षदों के आरक्षण की प्रक्रिया जारी है। वहीं नवगठित नगर पंचायत तमनार में वार्ड आरक्षण तथा बड़ी करेली में वार्ड परिसीमन एवं आरक्षण की कार्रवाई प्रगति पर है। विभाग द्वारा दो वार्ड पार्षद पदों पर आकस्मिक रिक्तियों की जानकारी भी बैठक में प्रस्तुत की गई।बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव श्रीमती शिखा राजपूत, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

छत्तीसगढ़ में ईवी चार्जिंग नेटवर्क को मिलेगा बूस्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से बढ़ाने का फैसला लिया है। मंत्रालय में सचिव सह-परिवहन आयुक्त श्री एस प्रकाश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में परिवहन विभाग, सभी आरटीओ/डीटीओ, ऊर्जा विभाग, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एलओसीएल, जिओ -बीपी, ईवी निर्माता और विशेषज्ञ मौजूद रहे।अभी अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग एप हैं, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। सरकार अब राज्य स्तर पर एकीकृत प्लेटफॉर्म/एप बनाएगी। भारत सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग एप ला रही है। चिप्स के जरिए ऊर्जा विभाग पहले ही पायलट एप पर काम कर रहा है। केंद्र की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन लगाने पर वित्तीय सहायता और छत्तीसगढ़ ईवी नीति-2022 के प्रोत्साहनों पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी जिलों के आरटीओ/डीटीओ को अपने क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह चिन्हित करने और एनओसी की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। एचपीसीएल, बीपीसीएल, एलओसीएल, जिओ -बीपी के निर्माताओं ने राज्य में लगे और प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी दी और आगे विस्तार की योजना बताया। सचिव सह-परिवहन आयुक्त ने कहा कि ईवी चार्जिंग का मजबूत नेटवर्क बनाना और लोगों को समय पर जानकारी देना जरूरी है। इससे हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

कैंसर से बचाने 13 से 18 जुलाई तक चलेगा टीकाकरण सप्ताह

रायपुर। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल कैंसर) और अन्य जननांग कैंसर से बचाता है। यह टीका 9 से 15 वर्ष की आयु के लोगों के लिए अनुशंसित है। इसे यौन गतिविधि शुरू होने से पहले लगवाना सबसे प्रभावी माना जाता है। खुराक की संख्या और समय-सीमा व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करती है । 9 से 14 वर्ष के बच्चों को 6-12 महीने के अंतराल पर 2 खुराक दी जाती हैं। 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को 6 महीने की अवधि में 3 खुराक की आवश्यकता होती है। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 13 से 18 जुलाई 2026 तक सुकमा जिले में विशेष एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण सप्ताह आयोजित किया जाएगा। इस अभियान के तहत 9 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में नि:शुल्क एचपीवी वैक्सीन लगाई जाएगी। छुट्टियांव मौसमी आयोजन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार एचपीवी संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण बन सकता है। समय पर लगाया गया एचपीवी टीका इस संक्रमण के खतरे को काफी हद तक कम करता है और भविष्य में गंभीर बीमारी से बचाव प्रदान करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि 9 से 15 वर्ष की आयु में लगाया गया एचपीवी टीका अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है। यह टीका न केवल सर्वाइकल कैंसर से बचाव करता है।

छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के कर्मियों को उपहार

रायपुर । स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के नवा रायपुर स्थित मुख्यालय भवन में निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू, की उपस्थिति में स्टेट वेयरहाउसिंग एवं ऐक्सिस बैंक के मध्य सैलरी एम ओ यू (समझौता ज्ञापन) निष्पादित किया गया। इस अवसर पर निगम के प्रबंध संचालक आषीष कुमार टिकरिहा साथ ही निगम एवं ऐक्सिस बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एम ओ यू (समझौता ज्ञापन) के तहत ऐक्सिस बैंक में निगम कर्मियों के सैलरी एकाउंट खोलने पर निगम के नियमित कर्मचारियों एवं दैनिक वेतन श्रमिकों को 1.10 करोड़ रूपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा तथा 10 लाख का प्राकृतिक मृत्यु बीमा नि:शुल्क कवर किया जाएगा। निगम कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में परिवार को 8 लाख रूपये तक की शिक्षा सहायता राशि प्रदान की जायेगी। साथ ही मात्र रूपये 2499/- के वार्षिक प्रीमियम पर रूपये 30 लाख तक का हेल्थ टॉप-अप कवर एवं 30 लाख का पर्सनल ऐक्सिडेंट कवर की सुविधा का लाभ भी मिलेगा। निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू ने बताया की इस एम ओ यू से कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों को बेहतर बैंकिंग, बीमा सुरक्षा तथा वित्तीय सुविधाएं प्राप्त होगी।

'यंग इंडियन पार्लियामेंट 2026' का हुआ आयोजन

रायपुर। राजधानी रायपुर के पुराने विधानसभा सभागार में यंग इंडियन पार्लियामेंट 2026 का आयोजन किया गया। यंग इंडियंस रायपुर चैप्टर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के 11 स्कूलों के करीब 150 छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। विधानसभा की तर्ज पर आयोजित इस मॉक पार्लियामेंट में बच्चों ने सदन की कार्यवाही को समझा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुभव किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका दी गई। बच्चों ने अपने-अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां की समस्याओं और जरूरतों को सदन के सामने रखा। देश और समाज से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा, बहस और तर्क-वितर्क के जरिए बच्चों ने अपनी बात रखी। इसके साथ ही मॉक पार्लियामेंट में विधेयक पेश करने और उसे पारित करने की प्रक्रिया भी कराई गई। यंग इंडियंस के पदाधिकारियों ने बताया कि स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी ही भविष्य में देश निर्माण की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को भारतीय लोकतंत्र, संविधान, संसदीय व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की भूमिका को व्यवहारिक रूप से समझाना है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य शूटिंग मीट 11 जुलाई से

रायपुर। 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य शूटिंग मीट का आयोजन छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल एसोसिएशन की ओर से 11 जुलाई से माना कैंप शूटिंग रेंज में होगा. राज्य शूटिंग मीट में 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर राइफल एवं पिस्टल स्पर्धाएँ आयोजित की जाएँगी, जिनमें प्रदेशभर के निशानेबाज विभिन्न श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे. यह प्रतियोगिता पहले 8 जुलाई से प्रस्तावित थी, लेकिन क्षेत्र में भारी वर्षा और मौजूदा मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए स्थगित करते हुए नई तारीख तय की गई है, जिससे सभी प्रतिभागियों और अधिकारियों की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित की जा सके. प्रतिभागी निशानेबाजों के लिए 12 जुलाई को एक प्रशिक्षण एवं अभ्यास सत्र आयोजित किया जाएगा. प्रशिक्षण सत्र के तुरंत बाद प्रतियोगिता मैच शुरू होंगे. एसोसिएशन संशोधित कार्यक्रम के तहत उत्साहपूर्ण भागीदारी और चैंपियनशिप के सफल आयोजन की आशा करता है।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध - कश्यप

संग्रहण पारिश्रमिक का समय पर हो रहा ऑनलाइन भुगतान

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 7.14 लाख से अधिक तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 162.32 करोड़ की प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) राशि का वितरण किया है। राज्य में वर्तमान में तेन्दूपत्ता संग्रहण की दर को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा किया गया है, जिससे संग्राहक परिवारों को सीधा आर्थिक संबल मिल रहा है। तेन्दूपत्ता का संग्रहण दर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा होने से संग्राहक परिवारों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार तेन्दूपत्ता संग्राहकों, वनवासियों और आदिवासी परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगल से जुड़े प्रत्येक श्रमिक को उसके श्रम का उचित सम्मान मिले और पारिश्रमिक समय पर सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचे।

वर्ष 2023 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण शुरू

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने बताया कि विगत 3 जुलाई को सहकारिता सप्ताह एवं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा वर्ष 2023 के तेन्दूपत्ता संग्रहण के प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण का शुभारंभ किया गया। इसके तहत

प्रदेश की 621 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों से जुड़े 7,14,446 तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 162.32 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। भुगतान की प्रक्रिया तेजी से जारी है और शीघ्र पूरी कर ली जाएगी।

वन मंत्री ने बताया कि सरकार ने संग्रहण सत्र 2026 में भी तेन्दूपत्ता संग्राहकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया है। प्रदेश के लगभग 11.15 लाख संग्राहकों को 734.25 करोड़ रुपए की संग्रहण पारिश्रमिक राशि ऑनलाइन माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। इससे लाखों वनवासी और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक मजबूती मिली है।

केदार कश्यप ने कहा कि तेन्दूपत्ता प्रदेश के लाखों वनवासी परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार है। इसलिए राज्य सरकार संग्रहण से लेकर भुगतान तक पूरी व्यवस्था को पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बना रही है, ताकि संग्राहकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को समय पर पारिश्रमिक और प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना इसी सोच का परिणाम है। आने वाले समय में भी सरकार वनवासियों के हितों की रक्षा, उनकी आय में वृद्धि तथा वन आधारित आजीविका को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।

डीएमएफ योजना से किसानों को मिली आधुनिक खेती की सौगात

रायपुर। जिला खनिज संस्थान न्यासयोजना के तहत खनन-प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को आधुनिक खेती, बेहतर सिंचाई और फसल भंडारण की सौगात मिल रही है। कृषि को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल कर कृषि अधोसंरचना और आजीविका को नई मजबूती दी जा रही है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला खनिज संस्थान न्यास योजना के तहत दंतेवाड़ा जिले के गीदम विकासखंड के 24 किसानों को पावर टिलर वितरित किए गए।

आधुनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा: पावर टिलर वितरण कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नंदलाल मुड़ामी ने किसानों को पावर टिलर की चाबी सौंपते हुए कहा कि आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती आसान होगी, लागत कम आएगी, समय की बचत होगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने किसानों से कृषि यंत्रों का बेहतर उपयोग कर आधुनिक खेती अपनाने की अपील की। पावर टिलर एक बहुउपयोगी कृषि यंत्र है। इसका उपयोग खेत की जुताई, मिट्टी की गुड़ाई, मेड़ बनाने, बुवाई, खरपतवार नियंत्रण तथा अन्य कृषि कार्यों में किया जा सकता है। यह विशेष रूप से छोटे और मध्यम किसानों के लिए काफी उपयोगी है, जिससे कम समय और कम श्रम में खेती के कार्य पूरे किए जा सकते हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पावर टिलर के उपयोग से खेती की लागत कम होगी।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.